प्रत्यक्ष करों के संग्रहण पर मास्टर परिपत्र

प्रस्तावना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित आयकर आयुक्तों के माध्यम से विभिन्न प्रत्यक्ष करों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। मुख्य आयकर आयुक्तों को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आयकर और निगम कर आदि के संग्रहण के साथ-साथ रिफंड आदि का कार्य सौंपा गया है।

2. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पी.सी.सी.ए.) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के लेखा संगठन का शीर्ष प्राधिकरण है। विभागीकृत प्रणाली के तहत, पी.सी.सी.ए., सीबीडीटी को प्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी प्राप्तियों और रिफंड के लेखांकन से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं। पी.सी.सी.ए. नई दिल्ली में बैठते हैं और देश भर में क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों (जेडएओ) के माध्यम से संचालित करते हैं। वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर 52 जेडएओ स्थित हैं।

3. प्रमुख लेखा शीर्ष

आयकर विभाग द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष करों को निम्नलिखित प्रमुख शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है:

i)	निगम कर (सी.टी.)	0020	निगम कर
ii)	आयकर (आई.टी.)	0021	निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर
iii)	संपत्ति कर (डब्ल्यू.टी.)	0032	धन पर कर
iv)	गिफ्ट कर (जी.टी.)	0033	गिफ्ट टैक्स

4. दिनांक 1 अप्रैल 1976 से पहले, आय और अन्य प्रत्यक्ष करों को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के कार्यालयों, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के शाखाओं, उनके सहयोगी जो सरकारी कारोबार करते हैं, कोषागार और उप-कोषागारों द्वारा स्वीकार किया जाता था। जनता के सदस्यों द्वारा इन करों को आसानी से जमा करने के केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के माध्यम से आयकर और अन्य प्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए एक योजना 1 अप्रैल 1976 से शुरू की गई थी।

5. 'प्रत्यक्ष करों के लिए लेखांकन प्रणाली' - संशोधित प्रक्रिया

लेखांकन और रिपोर्टिंग, प्रेषण में देरी और दस्तावेजों आदि को भेजने में देरी से संबंधित मामलों का अध्ययन करने के बाद, के बाद, 'सरकारी लेखों पर कार्य समूह' ने संशोधित प्रक्रिया का सुझाव दिया जो 1 अक्टूबर 1988 से लागू हुई। रिज़र्व बैंक ने सीबीडीटी बकायों की स्वीकृति और इसके लेखांकन और रिपोर्टिंग के बारे में अपने प्रकाशन "प्रत्यक्ष करों के लिए लेखांकन प्रणाली" के माध्यम से व्यापक अनुदेश जारी किए हैं, जिसे पिंक बुकलेट के रूप में जाना जाता है।

6. प्रत्यक्ष करदाताओं के लिए ग्राहक सेवा में सुधार करने की दृष्टि से प्रत्यक्ष करों के लेखांकन प्रणाली के लिए निम्नलिखित प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया था:

(i) टोकन जारी करना: हालांकि भुगतान की पावती के रूप में पेपर टोकन जारी करने के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश बहुत स्पष्ट हैं, फिर भी यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में अधिकृत शाखाएं ऐसे टोकन जारी नहीं करती हैं। कई स्थानों पर, अनौपचारिक व्यवस्था है जिसमें करदाता को बैंक शाखाओं से एक विशिष्ट तिथि के बाद चालान एकत्र करने के लिए कहा जाता है। कुछ मामलों में, प्राप्त चालान को सुरक्षित रूप से नहीं रखा जाता है और एक खुले बॉक्स में रखा जाता है। ग्राहकों को बिना किसी पहचान के स्वतंत्र रूप से अपने चालान लेने की अनुमति है। चेक या ड्राफ्ट के साथ जमा किए गए चालान के मामले में, पावती प्राप्त चालान चेक या ड्राफ्ट की राशि की वसूली पर जारी किए जाएंगे और इसलिए पेपर टोकन को उस तारीख को इंगित करना चाहिए जिस दिन चालान की प्रति प्राप्तियाँ तैयार रखी जाएंगी, ताकि करदाता टोकन में दी गई तारीख पर रसीद चालान लेने की व्यवस्था करे।

(ii) रसीदी चालान: रसीदी चालान को स्थानीय समाशोधन व्यवस्था के आधार पर 4-5 दिनों के भीतर निर्धारिती को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस निर्धारित प्रतीक्षा अवधि को पार नहीं किया जाए और इस संबंध में किसी भी विचलन को रिज़र्व बैंक द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। रसीदी चालानों को सावधानी के साथ और सुरक्षित तरीके से संभाला जाना चाहिए जब तक कि उन्हें संबंधित पेपर टोकन की प्रस्तुति पर काउंटर पर करदाता को नहीं सौंप दिया जाता है। किसी भी परिस्थिति में, प्राप्त चालान को ग्राहकों के लिए सुलभ खुले बॉक्स में नहीं रखा जाना चाहिए।

(iii) रसीदी चालान पर डबल डेट स्टम्प : यह पुन: बताया जाता है कि चालान पर दो तिथियां होनी चाहिए यानी चालान और लिखतों के 'प्रस्तुत करने की तारीख' और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित पिंक बुकलेट के अनुलग्नक-5 में निर्दिष्ट लिखतों की आय की 'वसूली की तारीख'।

(iv) समाशोधन चेक की स्वीकृति: यह देखा गया है कि कुछ बैंक कर प्राप्त करते समय अन्य बैंकों से लिए गए चेक स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक होते हैं जिसके परिणामस्वरूप चार्टर्ड एकाउंटेंट/कर सलाहकार अपने ग्राहकों की ओर से अपने स्वयं के चेक प्रस्तुत करते हैं। चूंकि अन्य बैंकों से प्राप्त चेक स्वीकार करने से ग्राहकों को बहुत सुविधा होगी, इसलिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उन ग्राहकों को वापस न करें जो अन्य बैंकों से प्राप्त चेक के साथ चालान जमा करते हैं।

(v) क्या करें और क्या न करें: पिंक बुकलेट के अनुबंध-4 में दी गई 'क्या करें' और 'क्या न करें' की सूची प्रत्यक्ष कर संग्रहण का काम करने वाले बैंक कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार प्रदान नहीं की जा रही थी। इसे शाखाओं को जारी किया जा सकता है।

7. ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (OLTAS)

7.1 जनवरी, 2003 में ओएलटीएएस की स्थापना के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का गठन किया गया था। एचपीसी ने ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली के लिए लेखा प्रक्रिया का सुझाव देने के लिए एक उप-समिति की स्थापना की। सीजीए और सीएजी द्वारा विधिवत अनुमोदित लेखा प्रक्रिया 01 जून, 2004 से ओएलटीएएस के लिए शुरू की गई थी। नई लेखांकन प्रक्रिया की मुख्य विशेषताओं में करदाता के काउंटरफॉइल को अलग करने के साथ एकल कॉपी चालान की शुरुआत, एकल कॉपी चालान पर चालान पहचान संख्या (सीआईएन) के रूप में जाना जाने वाला विशिष्ट सीरियल नंबर के साथ पावती स्टाम्प की ब्रांडिंग और करदाता के काउंटरफॉइल शामिल हैं। करदाता उनके द्वारा भुगतान किया गया कर को अब http://tin-nsdl.com पर लॉग इन करके देख सकते हैं। इसके अलावा, आयकर विभाग द्वारा अपेक्षित नई फाइल संरचना को भी ओएलटीएएस के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए एजेंसी बैंकों को भेज दिया गया था।

7.2 नई प्रक्रिया के तहत, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे समाशोधन चेक/ड्राफ्ट (यानी नकद और अंतरण चेक/ड्राफ्ट के अलावा) के साथ दिए गए चालानों के संबंध में पावती ऐसे चेक/ड्राफ्ट की राशि प्राप्ति के बाद ही जारी करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे ऐसे चालानों के संबंध में पेपर टोकन जारी करें जिसमें प्रस्तुत करने की तारीख और उस तारीख को दर्शाया जाए जिस दिन काउंटरफॉइल को सुपुर्दगी के लिए रखा जाएगा।

प्राप्तकर्ता बैंक को सलाह दी गयी थी की वे चेक-ड्राफ्ट की वसूली पर करदाताओं के काउंटरफोइल का टियर-ऑफ हिस्सा रबर स्टैम्प ब्रांडिंग व चालान पहचान संख्या (सी आई एन), जिसमे निम्नलिखित शामिल है, के साथ वापिस कर दें-

i. बैंक शाखा का बीएसआर कोड नंबर (7 अंक)
ii. चालान प्रस्तुत करने की तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाई)
iii. उस दिन उस शाखा में चालान का क्रम संख्या (5 अंक)

7.3 करदाता को नकदी या उसी प्राप्तकर्ता शाखा पर तैयार किए गए चेक के साथ प्राप्त चालान का टियर-ऑफहिस्सा उसी दिन निर्धारित रबर स्टैंप ब्रांडिंग द्वारा आवश्यक पावती के साथ वापस किया जा सकता है।

7.4 सभी गैर-कम्प्यूटरीकृत/गैर-नेटवर्क शाखाओं को यह सुनिश्चित करने की सूचना दी गयी थी कि उन शाखाओं से संबंधित डेटा को इसकी निकटतम कम्प्यूटरीकृत/नेटवर्क शाखा से नोडल शाखा और नोडल शाखा से लिंक सेल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाए, ताकि पूरे भारत में बैंक की सभी अधिकृत शाखाओं से संबंधित पूरा डेटा एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा होस्ट किए गए कर सूचना नेटवर्क (टिन) को निर्बाध रूप से प्रेषित किया जा सके।

7.5 जहां तक आयकर विभाग को स्क्रॉल और चालान भेजने का संबंध है,ओएलटीएएस के तहत नई लेखांकन प्रक्रिया मौजूदा प्रक्रिया की जगह लेगी। बैंकों को अग्रेषित ओएलटीएएस लेखांकन प्रक्रिया में प्रस्तावित परिवर्तनों को छोड़कर, पिंक बुकलेट "प्रत्यक्ष करों के लिए लेखांकन प्रणाली" (30 जून, 1999 तक अद्यतन) में निहित अनुदेश लागू रहेंगे।

7.6 इसके अलावा, जेडएओ और आयकर विभाग को पेपर स्क्रॉल और चालान भेजने की सामान्य प्रक्रिया के अलावा टिन को ऑनलाइन डेटा प्रसारित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था।

7.7 एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सुरक्षित दोतरफा संचार सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित लीज लाइन के साथ अपने लिंक सेल को मुंबई में टिन (एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) से जोड़ें।

8. एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डेटा का प्रेषण - सत्यापन जांच

8.1 बैंकों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों में एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड/आयकर विभाग द्वारा देखी गई विभिन्न प्रकार की त्रुटियों की सूचना बैंकों को दी गई है। विशेष रूप से पैन/टैन नंबर, गलत नोडल स्क्रॉल शाखा डेटा, आकलन वर्ष, करदाताओं का नाम न होना या गलत होना, सीआईएन नंबर, प्रमुख हेड कोड और राशि के संबंध में पाई गई डेटा एंट्री त्रुटियां बैंकों के ध्यान में लाई गई थी।

8.2 पाई गई कमियों के समाधान करने के लिए, एजेंसी बैंक सभी रिकॉर्ड प्रकारों के लिए ओएलटीएएस सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित सत्यापन जांच शामिल कर सकते हैं:

(i) RT01 और RT06 में फ़ील्ड NOD_BR_COL_SC_DT और NOD_BR_PYMT_SC_DT के लिए मान (यानी फ़ाइल नाम) क्रमशः 01-06-04 और प्रेषण की तारीख के बीच होना चाहिए।

(ii) पैन/टैन 10 अल्फान्यूमेरिक (अक्षरांकीय) वर्णों से कम का नहीं हो सकता है। यदि इसकी लंबाई 10 है तो पैन के मामले में पैन के पहले पांच और दसवां वर्ण केवल अक्षर (वर्ण) होना चाहिए, और छठे से नौवें यानी अगले चार संख्यात्मक अंक होने चाहिए। टैन के मामले में पहले तीन वर्ण सीटीयू कोड होने चाहिए और चौथे, दसवें को अक्षर (वर्ण) होना चाहिए और अगले पांच (पांचवें से नौवें) को संख्यात्मक होना चाहिए। पैन/टैन का उल्लेख 1 जनवरी, 2005 से अनिवार्य कर दिया गया है।

(iii) नाम विवरणी हमेशा अनिवार्य है और इसमें केवल अल्फ़ान्यूमेरिक (अक्षरांकीय) और बिन्दुओं का संयोजन होना चाहिए और यह एक से अधिक वर्णों का होना चाहिए (नाम स्ट्रिंग बिन्दुओं और संख्यात्मक या दोनों का नहीं होना चाहिए। मुख्य स्ट्रिंग में वर्णमाला होना चाहिए)। चालान पर पैन/टैन का उल्लेख किए जाने के बावजूद करदाता का **पूरा नाम** प्रेषित करना अनिवार्य है।

(iv) एक संग्रह शाखा का जेडएओ कोड नंबर स्थायी है और जेडएओ कोड नंबर का विवरण रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित पिंक बुकलेट में उपलब्ध है। नोडल शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह जेडएओ कोड नंबर रिकॉर्ड टाइप 01 में सही ढंग से उल्लिखित है और किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं किया गया है। यह सूचित किया जाता है कि सभी बैंकों को अपने ओएलटीएएस सॉफ्टवेयर में जेडएओ क्षेत्र में कोड को संचित करना चाहिए क्योंकि ऐसे प्रकरण आरबीआई/सरकार के ध्यान में लाए गए हैं जहां एक ही शाखा, प्रसारण की विभिन्न तिथियों पर अलग-अलग जेडएओ कोड का उल्लेख कर रही है।

8.3 उपर्युक्त सत्यापन जांचों के अतिरिक्त, बैंकों द्वारा निम्नलिखित पर्यवेक्षी कदम उठाए जाने हैं:

(i) संग्रहकर्ता बैंक के शाखा प्रबंधकों को चालान से कैप्चर किए गए नाम और राशि की सत्यता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए सभी बैंक शाखाओं में डाटा एंट्री की 'मेकर-चेकर' प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए।

(ii) सभी संग्रह शाखाओं को अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड टाइप 01 और रिकॉर्ड टाइप 02 (सारांश रिकॉर्ड) संचारित करना होगा, यदि उस दिन संग्रहण होता है। जिन शाखाओं में दिन के दौरान कोई संग्रहण नहीं हुआ है, वहां रिकॉर्ड टाइप 02 (शून्य विवरण) नोडल शाखा को प्रेषित किया जाना है। इससे टिन ओएलटीएएस के कार्यान्वयन की सटीक निगरानी कर सकेगा।

(iii) नोडल शाखा स्तर पर यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए कि सभी संग्रहकर्ता शाखाएं रिकॉर्ड टाइप 01 और रिकॉर्ड टाइप 02 को प्रसारित कर रही हैं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन संग्रहकर्ता शाखाओं का कोई संग्रह नहीं है, वे अपनी संबंधित नोडल शाखा को MAJ_HD_CD = 0 और TOT_AMT = 0 के साथ केवल रिकॉर्ड टाइप 02 (शून्य विवरण) प्रेषित करें।

(iv) नोडल शाखा के शाखा प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जेडएओ को प्रस्तुत किसी विशेष तिथि के नोडल शाखा स्क्रॉल में दिखाया गया प्रमुख शीर्षवार संग्रह, टिन को प्रस्तुत करने के लिए लिंक सेल को प्रेषित ओएलटीएएस डेटा में संबंधित योग से मेल खाना चाहिए। यह प्रक्रिया 1 जून, 2004 से सभी भुगतानों के संबंध में की जानी चाहिए।

(V) लिंक सेल स्तर पर सभी बैंकों को टिन को प्रेषित त्रुटि रिकॉर्ड पर की गई कार्रवाई का त्रुटि रिकॉर्डबनाए रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि वह सभी रिकॉर्ड जिन्हें प्रारंभ में कुछ कमियों के कारण टिन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और उन्हे 48 घंटों के भीतर कमियों को दूर करने के बाद अनिवार्य रूप से टिन में पुनः संचारित कर दिया गया है।

(vi) यह देखा गया है कि बैंक गलत प्रमुख शीर्ष कोड दर्ज कर रहे हैं यानी प्रमुख शीर्ष 020 के तहत प्राप्त भुगतान को निगम कर के लिए और प्रमुख शीर्ष 021 को निगम कर के अलावा आयकर कर के लिए परस्पर परिवर्तित कर दिया गया है। इससे भुगतानों का परिहार्य गलत वर्गीकरण होता है और आयकर विभाग और जेडएओ के बीच खातों के मिलान को प्रभावित होता है। वैध पैन के मामले में, उपरोक्त सत्यापन को ओएलटीएएस सॉफ्टवेयर में शामिल किया जा सकता है यानी यदि 4$^{वां}$ वर्ण (बाईं ओर से) 'सी' है तो प्रमुख शीर्ष कोड 020 होना चाहिए।

8.4 आयकर विभाग ने हमें यह भी सूचित किया है कि आकलन वर्ष के आंकड़ों को प्रेषित करते समय, बैंकों को सामान्य और ब्लॉक मूल्यांकन वर्षों के लिए पहले भाग को प्रेषित करना आवश्यक था; उदाहरण के लिए सामान्य आकलन वर्ष 2005 - 2006 के लिए बैंक को 2005 को प्रेषित करना आवश्यक है और 1997-2005 जैसे ब्लॉक मूल्यांकन वर्ष के लिए वर्ष 1997 को प्रेषित किया जाना चाहिए।

9. ज़ेडएओ को ई-मेल द्वारा दैनिक स्क्रॉल भेजना

बैंकों को प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए इलेक्ट्रॉनिक नोडल शाखा दैनिक मुख्य स्क्रॉल के संशोधित प्रारूप की सूचना दी गई थी। संशोधित प्रारूप **(अनुबंध III)** का उपयोग सभी प्राप्तकर्ता शाखाओं से भौतिक चालान/स्क्रॉल प्राप्त होने तक सभी जेडएओ को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दैनिक मुख्य स्क्रॉल भेजने के लिए किया जाना है।

10. सीबीडीटी बकाया के संग्रहण के लिए उप-एजेंसी व्यवस्था का उन्मूलन

यह देखा गया कि ओएलटीएएस के तहत डेटा अपलोड नहीं करने के प्रमुख कारणों में से एक उस इलाके में एक अन्य प्रमुख बैंक के साथ उप-एजेंसी व्यवस्था का होना है जहां संबन्धित उप एजेंसी बैंक के पास, सीबीडीटी द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार, अपनी नोडल शाखा रखने के लिए पर्याप्त संख्या में शाखाएं नहीं हैं। अनुकूलता न होने या अन्य कारणों से उप-एजेंसी व्यवस्था के तहत शाखाओं द्वारा प्राप्त चालानों की पुनरावृत्ति में डेटा कई मामलों में प्रधान एजेंसी बैंकों द्वारा टिन पर अपलोड नहीं किया गया था। उप-एजेंसी व्यवस्थाओं से उत्पन्न होने वाली देरी और समस्याओं से बचने के लिए, आयकर निदेशालय (सिस्टम), नई दिल्ली के परामर्श से उप-एजेंसी व्यवस्था को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है। बैंकों को सूचना दी गई थी कि वे, जहां भी उनकी शाखाएं उप-एजेंसी व्यवस्थाओं के तहत कार्य कर रही हैं, वहाँ अपनी नोडल शाखाएं नामित करें।

11. निधि का निपटान - आरबीआई, सीएएस नागपुर को रिपोर्ट करना

11.1 1 अप्रैल 2005 से टिन पर अपलोड किए गए ऑन लाइन आंकड़ों के आधार पर निधियों के निपटान के निर्णय को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के लेन-देनों की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएएस, नागपुर को देने की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा की गई है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि एजेंसी बैंक सीबीडीटी के आंकड़े आरबीआई, सीएएस, नागपुर को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-मेल (द्वितीय श्रेणी प्रमाण पत्र धारक द्वारा हस्ताक्षरित) के माध्यम से अलग से प्रस्तुत करेंगे। सीबीडीटी के आंकड़े जिनहे टिन को सप्ताह के दिनों में 13.15 बजे के और शनिवार को दोपहर 12.30 बजे तक रिपोर्ट किया गया उन्हे डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-मेल के माध्यम से निधि निपटान के लिए सीएएस, नागपुर को भी साथ के साथ सूचित किया जाएगा। कट-ऑफ समय के बाद मेल किए गए डेटा को सीएएस, नागपुर द्वारा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11.2 बैंकों को सूचित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएएस की प्रणाली द्वारा किसी भी अस्वीकृति का उसी दिन हिसाब नहीं दिया जाएगा क्योंकि वर्तमान में लिंक सेल से संशोधित सलाह प्राप्त करने के बाद ऐसा किया जा रहा है। सीएएस में सिस्टम द्वारा स्वीकार किए गए आंकड़े का हिसाब किया जाएगा। अस्वीकृति रिपोर्ट उसी दिन दैनिक इनपुट स्टेटमेंट के साथ लिंक सेल को दी जाएगी। बैंकों को इस संबंध में अपनी शाखाओं और लिंक सेल को आवश्यक अनुदेश जारी करने की सूचना दी गई थी।

11.3 यह स्पष्ट किया गया था कि निधियों के निपटान के लिए किसी भी तारीख को सीएएस, नागपुर में अपलोड की गई वित्तीय डेटा फाइल और टिन पर अपलोड किया गया उस विशेष निपटान तिथि से संबंधित चालान डेटा बिल्कुल मेल खाना चाहिए। एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा बाद में अस्वीकार की गई फाइलें, यदि कोई हों, सत्यापन त्रुटियों आदि के कारण, अलग से संसाधित की जानी चाहिए और फिर से अपलोड की जानी चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सूचना दी गई थी कि करदाता द्वारा जमा किए गए प्रत्येक चालान के संबंध में चालान डेटा अपलोड किया गया है और टिन द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है। टिन में फाइलों को दोबारा अपलोड करने से फंड सेटलमेंट डेटा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टिन की पूरी रिपोर्टिंग की आवश्यकता तब होगी जब लिंक सेल से सीएएस, नागपुर में जाने वाले डेटा और टिन में जाने वाले सापेक्ष चालान डेटा को **एक साथ अपलोड किया जाता है।**

11.4 लिंक सेल को यह सुनिश्चित करने की सूचना दी गई थी की अपलोडिंग तिथि के लिए सीएएस और टिन पर अपलोड किए गए आंकड़ों में कोई विसंगति न हो।

11.5 नोडल शाखाओं को ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओएलटीएएस) से संबंधित लेखा प्रक्रिया के पैरा 6 में निहित अनुदेशों का सावधानीपूर्वक पालन करने की सूचना दी गई थी और संबंधित क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों को दैनिक आधार पर स्क्रॉल और चालान आदि भेजने की भी सूचना दी गई थी।

12. ओएलटीएएस पर स्पष्टीकरण

ओएलटीएएस के संबंध में बैंकों को मार्गदर्शन के लिए आरबीआई द्वारा जारी किए गए कतिपय स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं :

12.1 चालान पहचान संख्या (सीआईएन)

यह स्पष्ट किया गया कि ओएलटीएएस लेखांकन प्रक्रिया (अनुबंध) के पैराग्राफ 1.3.3 के अनुसार सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों में एक विशेष दिन पर नकद, हस्तांतरण चेक के साथ-साथ **चेक समाशोधन** के साथ प्रस्तुत किए गए सभी चालानों के लिए क्रम संख्या देना होगा। जबकि नकद और हस्तांतरण चेक

(यानी संग्रह शाखा पर आहरीत चेक) के एक हिस्से को निविदाकर्ता को निर्धारित रबर स्टैंप के साथ वापस करने की आवश्यकता होती है, जिसमें निविदा की तारीख, बीएसआर कोड और सीआईएन आदि का उल्लेख होता है, **समाशोधन चेक** के साथ प्रस्तुत चालान (अर्थात अन्य शाखाओं/बैंकों पर आहरित) लिखतों की प्राप्ति पर ही लौटाना होगा। प्राप्तकर्ता बैंक शाखा के अधिकृत अधिकारी को चालान के टियर-ऑफ हिस्से के साथ-साथ मूल चालान पर हस्ताक्षर करने की भी आवश्यकता थी।

12.2 बैंकों से अनुरोध किया गया था कि वे ओएलटीएएस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के लिए आयकर वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर जाएं।

13. इसके अलावा, बैंकों को अधिकृत शाखाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने की सूचना दी गई थी कि प्रत्येक चालान रिकॉर्ड प्रत्येक शाखा, जहां कर संग्रह किया गया है, द्वारा टिन को प्रेषित किया जाए। यह पुन: दोहराया जाता है कि नोडल शाखा को, जब दिन के दौरान कोई कर संग्रह नहीं हुआ हो, एक शून्य विवरण (रिकॉर्ड टाइप 02) प्रेषित किया जा सकता है था ताकि टिन ओएलटीएएस की ठीक से निगरानी कर सके। इस बात पर भी जोर दिया गया कि टिन को प्रेषित डेटा सही और पूर्ण होना चाहिए और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप होना चाहिए।

14. बैंकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियों के बारे में सूचित किया गया था जिन्हें आयकर निदेशालय द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में लाया गया था :

ए) बैंको द्वारा पैन/टैन का अभिग्रहण नहीं किया जाना - कई केंद्रों से यह रिपोर्ट किया गया था कि जहां करदाता ने अपने पैन को सही तरीके से उद्धृत किया है, वहां भी कुछ बैंक शाखाएं या तो इसे दर्ज नहीं कर रही थीं या इसे अधूरे तरीके से दर्ज कर रही थीं। इस संबंध में, बैंकों को सूचित किया गया कि ऑन-लाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम (ओएलटीएएस) प्रक्रिया/नियमों के तहत यह निर्धारित किया गया है कि *जहां भी* करदाता द्वारा *उचित अल्फा न्यूमेरिक* (अक्षरांकीय) संरचना *में 10 अंकों* का *पैन/टैन उद्धृत किया जाता है, बैंकों को केवल पैन और करदाता का नाम* लेना होगा, *पते का नहीं।*

बी) करदाता का पूरा नाम का अभिग्रहण नहीं किया जाना - टिन पर अपलोड किए गए डेटा के अवलोकन से संकेत मिलता है कि कई बैंक शाखाएं अभी भी करदाता के नाम कॉलम में एक या दो अक्षर डाल रहे हैं। कुछ मामलों में प्रतीकों और बिंदुओं का भी उपयोग किया गया था। बैंक कृपया ओएलटीएएस डेटा में करदाता का पूरा नाम अभिग्रहीत करना सुनिश्चित कर सकते हैं।

सी) गलत पता - विश्लेषण किए गए डेटा से यह भी पता चलता है कि कई बैंक शाखाओं द्वारा पतों के स्थान को ठीक से अभिग्रहण नहीं किया जा रहा था। कई मामलों में, केवल कुछ यादृच्छिक वर्णमाला या संख्याएं दर्ज की जा रही थीं जो फिर से इंगित करती हैं कि बैंक शाखाएं पूर्ण डेटा कैप्चर के लिए पर्याप्त देखभाल नहीं कर रही हैं। बैंकों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई थी।

डी) चालान पहचान संख्या (सीआईएन) की गलत रिपोर्टिंग – कुछ बैंक शाखाएं करदाता के काउंटरफॉइल पर एक विशेष चालान पहचान संख्या (सीआईएन) आवंटित कर रही थीं, लेकिन भेजे गए ओएलटीएएस डेटा पर एक अलग सीआईएन दर्ज कर रही थीं। ओएलटीएएस प्रक्रिया/नियमों के अनुसार, सीआईएन को केवल प्रस्तुतीकरण की तारीख पर आवंटित किया जाना था। करदाता के काउंटरफॉइल के साथ-साथ चालान के मुख्य भाग पर अंकित सीआईएन नंबर को टिन में प्रेषित किया जाना चाहिए।

ई) गैर-समान स्क्रॉल डेटा - ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रक्रिया / नियमों के अनुसार, किसी विशेष दिन के लिए नोडल शाखा का स्क्रॉल दोनों जेडएओ के साथ-साथ ओएलटीएएस पर टिन को प्रेषित डेटा के लिए समान होना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया कि किसी विशेष दिन के लिए जेडएओ और टिन को भेजे

जा रहे सभी संग्रह डेटा चालान की संख्या और प्रमुख शीर्षों के संबंध में मेल खाना चाहिए। इसके अलावा बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सूचना दी गई कि प्रत्येक शाखा,जहां संग्रहण किया गया है, द्वारा टिन को **प्रत्येक** चालान रिकॉर्ड भेजा जाए।

15. प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए बैंक शाखाओं का प्राधिकरण रद्द

15.1 ओएलटीएएस के तहत अधिकृत बैंक शाखाओं की सूचीबद्धता समाप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, कार्यालय प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीसीसीए), सीबीडीटी, नई दिल्ली के कार्यालय के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि शाखाओं के गैर-प्राधिकरण के लिए कोई भी प्रस्ताव एजेंसी बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित मापदंडों/दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

i) मौजूदा शाखा को पिछले वर्ष (अप्रैल-मार्च) में कोई प्रत्यक्ष कर प्राप्त नहीं हुआ है।

ii) प्राधिकृत शाखा की सूचीबद्धता समाप्त करने के प्रस्ताव को संबंधित बैंक के शीर्ष अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

15.2 भारतीय रिजर्व बैंक/पी.सी.सी.ए., सीबीडीटी के कार्यालय द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने के बाद संबंधित बैंक को इस आशय का व्यापक प्रचार करना चाहिए कि विशिष्ट शाखा एक विशिष्ट भावी तिथि से करों की स्वीकृति बंद कर देगी और तदनुसार हमें सूचित करेगी।

16. कर सूचना नेटवर्क द्वारा विकसित फ़ाइल पृथक्करण उपयोगिता

कुछ बैंकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (टिन) को कुछ गलत रिकॉर्ड के कारण बैंक के लिंक सेल से प्राप्त ओएलटीएएस डेटा की पूरी फाइल को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। बैंकों ने इच्छा व्यक्त की है कि गलत रिकॉर्ड को अस्वीकार करते हुए टिन को उन अभिलेखों को स्वीकार करना चाहिए जो सही सत्यापन के साथ हैं। एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (टिन) और बैंकों के साथ सीबीडीटी की चर्चा के आधार पर, टिन ने एक फाइल पृथक्करण उपयोगिता विकसित की थी, जिसे बैंकों को सूचित किया गया। (अनुबंध II)

17. सीबीडीटी संग्रहण को सरकारी खाते में जमा करने से संबंधित लेखा प्रक्रिया – सार्वजनिक क्षेत्र के एजेंसी बैंक

17.1 भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 2005 से टी+3 दिनों (रविवार और छुट्टियों सहित) के बजाय **टी+3 कार्य** दिवसों (जहां टी वह दिन है जब बैंक शाखा को धन उपलब्ध होता है) में कर संग्रह जमा करने के लिए अनुमत अधिकतम दिनों से संबंधित अनुदेशों में संशोधन किया जाए। कार्य दिवसों की गणना के लिए सीएएस, नागपुर के अवकाश सूची का संदर्भ लिया जाएगा।

17.2 यह निर्णय लिया गया है कि सीएएस, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ निपटान की तारीख को टी+3 कार्य दिवसों की मौजूदा समय सीमा से बाहर रखा जाएगा।

17.3 विलंबित अवधि के लिए बैंकों पर ब्याज लगाया जाएगा न कि लेनदेन की तारीख से। दूसरे शब्दों में, 'देरी अवधि' गणना 'पुट थ्रू डेट' के बाद से शुरू होगी।

17.4 एक लाख रुपये और उससे अधिक के लेनदेन में देरी की अवधि पर बैंक दर + 2% पर विलंबित अवधि ब्याज लगेगा। बैंक दर वह दर होगी जिसे आरबीआई द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा रहा है।

17.5 एक लाख रुपये से कम के लेनदेन के लिए, विलंबित अवधि ब्याज 5 कैलेंडर दिनों तक बैंक दर पर और 5 कैलेंडर दिनों से अधिक की देरी पर **देरी की पूरी अवधि के लिए** बैंक दर + 2% पर लगाया जाएगा। बैंक दर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित दर होगी जो लेनदेन के समय लागू होती है।

17.6 मंत्रालयों/विभागों में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीसीसीए), मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) और लेखा नियंत्रक (सीए) बैंकों द्वारा किए गए सभी विप्रेषणों की तिमाही समीक्षा करते हैं। यदि बैंक के पास लगातार दो तिमाहियों में समग्र रूप से या उसकी किसी भी शाखा के साथ 5% या उससे अधिक की दर पाई जाती है, तो संबंधित बैंक या शाखा के लिए प्राधिकरण को पीसीए/सीसीए/सीए की सिफारिशों के साथ समीक्षा के लिए सीजीए को भेज दिया जाएगा। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्वयं के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का निर्माण करें ताकि बैंक द्वारा अपनी शाखाओं के लिए निवारक और सुधारात्मक कार्रवाई समय पर की जा सके।

18. सरकारी खाता में सीबीडीटी संग्रहण को क्रेडिट करने से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया – निजी क्षेत्र के एजेंसी बैंक

18.1 निजी क्षेत्र के एजेंसी बैंकों के मामले में सीएएस, नागपुर के साथ लेनदेन को निपटाने की समय सीमा **टी + 3 दिन (रविवार और छुट्टियों सहित)** बनी रहेगी। विलंब की अवधि को प्राप्तकर्ता शाखा (बैंक में धन की वास्तविक वसूली) में संग्रह की प्राप्ति से तब तक गिना जाएगा जब तक कि इसे सरकारी खाते में क्रेडिट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएएस, नागपुर को सूचित नहीं किया जाता है। विलंबित अवधि का ब्याज बैंकों से वसूल किया जाएगा जिसमें शामिल राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। विलंबित अवधि ब्याज मौजूदा बैंक दर + 2% पर लगाया जाएगा। (बैंक दर समय-समय पर आरबीआई द्वारा अधिसूचित की जाएगी)।

18.2 इसके अलावा, ऊपर पैरा 17.6 में दिए गए निर्देश निजी क्षेत्र के एजेंसी बैंकों पर भी लागू होंगे।

19. करदाताओं द्वारा चेक तैयार करना- भुगतानकर्ता का नाम

ओएलटीएएस के तहत प्रत्यक्ष कर भुगतान के लिए चालान जमा करने के लिए करदाताओं द्वारा चेक/डीडी लेते समय भुगतानकर्ता के नाम में एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से आयकर विभाग द्वारा आयकर चालान के पीछे निम्नलिखित अनुदेश मुद्रित करने का निर्णय लिया गया है-

करदाता आयकर के भुगतान के लिए चेक/डीडी जारी कर सकते हैं:

"भुगतान करें... (उस बैंक का नाम जहां चालान जमा किया जा रहा है) - आयकर विवरण"।

बैंकों को अपनी सभी अधिकृत शाखाओं के संज्ञान में बदलाव लाना चाहिए।

20. प्रमुख शीर्ष / चालान

बैंकों को भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए संशोधित चालान प्रारूपों के बारे में सूचित किया गया था, जो दो नए करों यानी **फ्रिंज बेनिफिट टैक्स** और ***बैंकिंग नकद लेनदेन कर*** की शुरुआत के कारण आवश्यक थे। आयकर विभाग द्वारा प्रमुख शीर्षों और उप-लघु लेखा शीर्षों के लिए किए गए परिवर्तन/युक्तिकरण नीचे दिए गए हैं:

चालान संख्या आईटीएनएस - 280

चालान दो प्रमुख शीर्षों के तहत भुगतान के लिए है अर्थात (ए) कंपनियों पर 0020 आयकर (निगम कर) और (बी) 0021 आयकर (कंपनियों के अलावा)। करदाताओं के लिए अब लगातार आकलन वर्षों के अलावा अन्य आकलन वर्षों के लिए करों का भुगतान करना संभव होना चाहिए। उदाहरण के लिए, ब्लॉक अवधि (लगातार एक से अधिक मूल्यांकन वर्ष) के लिए आकलन के मामले में, बैंक के सॉफ्टवेयर में मूल्यांकन वर्ष क्षेत्र को लगातार मूल्यांकन वर्ष के अलावा किसी अन्य अवधि के लिए भुगतान स्वीकार करने के लिए संशोधित किया जा सकता है उदाहरण के लिए लेखा वर्ष 1991-97, 1992-99, 1993-99 आदि के लिए भुगतान।

चालान संख्या 281

चालान टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती)/टीसीएस (स्रोत पर कर एकत्र) के भुगतान के लिए है। इसमें दो प्रमुख शीर्ष है यानी (ए) कंपनी कटौतीकर्ताओं के लिए 0020 और (बी) गैर-कंपनी कटौतीकर्ताओं के लिए 0021। चालान में दो लघु शीर्ष कोड हैं जो करदाता द्वारा निर्धारित किए जाते हैं (क) करदाता द्वारा देय टीडीएस/टीसीएस (लघु शीर्ष-200) (ख) नियमित मूल्यांकन पर टीडीएस/टीसीएस (आयकर विभाग द्वारा उठाया गया) (लघु शीर्ष-400)।

चालान में अब प्रस्तुत किए गए नए तीन अंकों के कोड उप लघु शीर्ष निम्नानुसार हैं:

धारा	भुगतान की प्रकृति	कोड
206C	मानव के उपभोग के लिए मादक पदार्थ से स्रोत पर संग्रहण	6 C A
206C	वन पट्टे के तहत प्राप्त लकड़ी से स्रोत पर संग्रहण	6 C B
206C	वन पट्टे के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त लकड़ी से स्रोत पर संग्रहण	6 C C
206C	किसी अन्य वन उपज से स्रोत पर संग्रहण (तेंदू पत्ते नहीं)	6 C D
206C	स्क्रैप से स्रोत पर संग्रहण	6 C E
206C	ठेकेदारों या लाइसेंसधारक से स्रोत पर संग्रहण या पार्किंग स्थल से संबंधित पट्टे	6 C F
206C	ठेकेदारों या लाइसेंसधारक से स्रोत पर संग्रहण या टोल प्लाजा से संबंधित पट्टे	6 C G
206C	ठेकेदारों या लाइसेंसधारक से स्रोत पर संग्रहण या खदान से संबंधित पट्टे	6 सी एच
206C	तेंदू पत्तों से स्रोत पर संग्रह	6 CI

चालान संख्या 282

यह चालान कई करों के भुगतान के लिए है। इस चालान में किए गए परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

a) प्रतिभूति लेनदेन कर को पूर्व प्रमुख शीर्ष 0025 के स्थान पर प्रमुख शीर्ष 0034 की संख्या दी गयी है।
b) वेल्थ-टैक्स - इस चालान में प्रमुख शीर्ष 0032 को शामिल किया गया है। इससे पहले यह प्रमुख शीर्ष चालान नंबर 280 में था।

चालान संख्या 283

आकलन वर्ष 2010-11 से फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को समाप्त करने और 1 अप्रैल, 2009 से बैंकिंग नकद लेनदेन कर की वापसी के परिणामस्वरूप, यह चालान वर्तमान में उपयोग में नहीं है।

बैंक कृपया ओएलटीएएस सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन की व्यवस्था कर सकते हैं और उपरोक्त परिवर्तनों को प्रत्यक्ष कर एकत्र करने वाली सभी शाखाओं के ध्यान में ला सकते हैं ताकि शाखाएं तत्काल प्रभाव से इन करों का भुगतान स्वीकार कर सकें।

21. पैन/टैन का सत्यापन

आयकर विभाग अपने क्षेत्रीय कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से सभी एजेंसी बैंकों की नोडल शाखाओं को पैन/टैन मास्टर और उस क्षेत्र के करदाताओं के नाम वाली एक सीडी प्रदान करेगा, जिसे तिमाही आधार पर अपडेट किया जाएगा। बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी शाखाओं को आंतरिक वितरण के लिए सीडी की प्रतियों को एक सरल डेटा पुनर्प्राप्ति सॉफ्टवेयर के साथ दोहराएं जिसका उपयोग दिये गए चालान में कर दाता द्वारा उद्धृत पैन/ टैन का क्रॉस सत्यापन के लिए किया जा सकता है। बैंकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने की संभावना का पता लगाएं, जिससे पैन/टैन और सीडी में दिया गया नाम स्वचालित रूप से उनकी डेटा एंट्री प्रणाली द्वारा कैप्चर हो जाए, जिससे पैन/टैन की अलग-अलग डेटा प्रविष्टि समाप्त हो जाए। यदि करदाता का पैन/टैन सीडी में उपलब्ध नहीं है, तो ग्राहक से पैन /टैन की सार्थकता को इंगित करने के लिए संबंधित पैन/टैन कार्ड या किसी अन्य दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जा सकता है। बैंकों को उन मामलों में सत्यापन के प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने वाले इन दस्तावेजों को अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है जहां कर दाता का पैन/टैन क्षेत्रीय कंप्यूटर केंद्र द्वारा प्रदान की गई सीडी में उपलब्ध नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों को सूचित किया गया था कि वे संबंधित प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा दृश्य जांच के बिना चालान स्वीकार न करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चालान में वैध 10 अंकों के में पैन / टैन है।

22. दिनांक 1/1/2005 से चालान पर स्थायी खाता संख्या (पैन)/कर कटौती खाता संख्या (टैन) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना

करदाताओं को सही और शीघ्र जमा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), भारत सरकार ने दिनांक **01 जनवरी 2005** से चालानों पर पैन/टैन का उल्लेख अनिवार्य करने के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बैंक शाखाओं द्वारा करों का कोई भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि करदाताओं के पैन को चालान आईटीएनएस 280 और 282 या चालान आईटीएनएस 281 पर कटौतीकर्ता के टैन पर उद्धृत नहीं किया जाता है, जैसा भी मामला हो। शाखाएं एक नोटिस प्रदर्शित कर सकती हैं जिसमें कहा गया हो कि **1-1-2005 से शाखाओं में चालान पर पैन/टैन का उल्लेख करना अनिवार्य है** और उस तारीख से पैन/टैन के बिना चालान स्वीकार नहीं करना है। पैन/टैन प्राप्त करने की प्रक्रिया आयकर विभाग (http://www.incometaxindia.gov.in या http://www.tin-nsdl.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शाखाएं करदाताओं को कर जमा करने से पहले पैन/टैन प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन कर सकती हैं। चालान फॉर्म संख्या 12000 को अपलोड करने की सुविधा पूर्व-मुद्रित पैन/टैन नंबर के साथ 280 और 281 को भी आपकी नामित शाखाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जा सकता है।

23. ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (OLTAS) - डेटा गुणवत्ता में सुधार

23.1 टिन पर अपलोड किए गए चालान विवरण में विसंगतियां

एजेंसी बैंकों द्वारा टिन पर अपलोड किए गए ओएलटीएएस डेटा अक्सर कटौतीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत टीडीएस/टीसीएस रिटर्न के माध्यम से प्रस्तुत सापेक्ष डेटा से मेल नहीं खाते हैं। देखी गई सामान्य अनियमितताएं निम्न थीं:

a) ओएलटीएएस के माध्यम से अपलोड किए गए आंकड़ों में प्राप्ति की तारीख को चालान निविदा तिथि के रूप में डिजिटाइज किया गया है।

b) गलत चालान क्रमांक संख्या, मेजर हेड, पैन/टैन आदि अपलोड करना।

c) चालान काउंटरफॉइल पर चालान सीरियल नं. मुहर नहीं लगाई गई।

d) एकल चालान के खिलाफ इंगित राशि को दो राशियों में विभाजित किया गया है और दो चालानों में रिपोर्ट किया गया है।

बैंकों को सूचित किया गया था कि वे उपरोक्त त्रुटियों से बचें और ओएलटीएएस डेटा को कैप्चर और अपलोड करते समय अधिक सावधान रहें।

23.2 डेटा गुणवत्ता से संबन्धित मामले

पैन और सीआईएन को टिन में रिपोर्ट करने में सटीकता प्राप्त करने के लिए एजेंसी बैंकों को सलाह दी गई थी :

ए) टिन-एनएसडीएलई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड साइट से थोक पैन सत्यापन सुविधा का उपयोग करें;

बी) जब भी आवश्यक हो पैन के प्रमाण पर जोर दें और

सी) सुनिश्चित करें कि ग्राहक को दिया गया सीआईएन ओएलटीएएस पर अपलोड किया गया हो। विशेष रूप से निविदा की तारीख के संदर्भ में सावधानी बरती जानी चाहिए।

24. कम्प्यूटरीकृत प्राप्तियों की शुरूआत और डेटा गुणवत्ता में सुधार

एजेंसी बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे 01 जून, 2008 से निर्धारित प्रोफार्मा अर्थात् अनुलग्नक ए-IV-I और II के अनुसार संगत आंकड़ों सहित ओएलटीएएस लेनदेनों के चालान भुगतान के लिए कम्प्यूटरीकृत रसीदें जारी करें। एजेंसी बैंकों को निम्नानुसार अतिरिक्त दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है:

I) **डेटा एंट्री का मेकर चेकर सिस्टम:** मेकर चेकर सिस्टम जिसमें गलत डेटा एंट्री की संभावना को दूर करने के लिए एक द्वारा डेटा एंट्री को दूसरे द्वारा चेक किया जाता है, का सख्ती से पालन किया जा सकता है।

ii) सॉफ्टवेयर अलर्ट: डेटा एंट्री त्रुटि को कम करने के लिए, संग्रहकर्ता शाखाओं में डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर को चेतावनी संदेश प्रदान करना चाहिए जहां पैन / टैन दर्ज नहीं किया गया है या संरचनात्मक रूप से

अमान्य डेटा दर्ज किया गया है या पैन को टैन के लिए बनाए गए कॉलम में दर्ज किया गया है या जहां लघु शीर्ष और मूल्यांकन वर्ष आदि के बीच बेमेल है।

iii) **सॉफ्टवेयर सत्यापन:** आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए सॉफ़्टवेयर सत्यापन आपके सिस्टम में शामिल किए गए हैं।

iv) **बैंक स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन**: सभी एजेंसी **बैंकों** से सरकारी कर के संग्रह के संबंध में गुणवत्ता आश्वासन की उम्मीद की जाती है।

v) **अस्वीकृत फ़ाइल का पुन: अपलोड**: एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में डेटा फ़ाइल की अस्वीकृति को समाप्त करने के लिए टिन पर अपलोड करने से पहले ओएलटीएएस डेटा फ़ाइल को फ़ाइल सत्यापन उपयोगिता (एफवीयू) के माध्यम से मान्य किया जा सकता है।

25. सरकारी राजस्व से संबंधित ई-भुगतान लेनदेन के लिए समय में कटौती

एजेंसी बैंकों द्वारा रात 8.00 बजे तक प्राप्त ओएलटीएएस के तहत भुगतान को उसी दिन प्राप्त माना जा सकता है और उसके बाद प्राप्त भुगतान को अगले कार्य दिवस पर प्राप्त माना जा सकता है।

26. करदाताओं की कुछ श्रेणियों द्वारा कर का अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान

सीबीडीटी ने करदाताओं की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए करों का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अनिवार्य कर दिया है:

ए) एक कंपनी

बी) एक व्यक्ति (एक कंपनी के अलावा) जिस पर धारा 44एबी के प्रावधान लागू होते हैं

इसलिए, बैंक अपनी शाखाओं को निर्देश दे सकते हैं:

ए) नाम से कॉर्पोरेट करदाताओं की स्थिति की पहचान करना। सभी कॉर्पोरेट कर्मचारियों के पैन का चौथा अंक "सी" होगा। इसलिए ऐसे निरीक्षकों के भौतिक चालान को काउंटर पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

बी) आईटी अधिनियम की धारा 44एबी के तहत करदाताओं से बैंक काउंटरों पर भौतिक चालान स्वीकार करना क्योंकि ई-भुगतान करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से करदाताओं की है।

सी) स्क्रीन पर तुरंत ई-भुगतान के लिए पावती उपलब्ध कराना।

डी) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ई-भुगतान की लेनदेन आईडी बैंक के विवरण में परिलक्षित होती है।

ई) यदि करदाता को भुगतान करने, ई-भुगतान लेनदेन को पूरा करने, काउंटरफॉइल उत्पन्न करने आदि में किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो जिस अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं उसकी सूचना अपने ई-भुगतान गेटवे पेज पर प्रदर्शित करनी चाहिए।

एफ) आईटीडी और एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को आईटीडी या करदाताओं के सामने आने वाली किसी भी समस्या के लिए आवश्यक होने पर संपर्क विवरण के साथ अधिकारियों की

एक सूची देने के लिए।

एजेंसी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए आईटी अधिनियम की धारा 44एबी के तहत आने वाले करदाताओं के नामों और क्षेत्रवार पैन और नामों वाली एक सीडी प्रदान की गई थी और आईटी अधिनियम की धारा 44एबी के तहत आने वाले करदाताओं द्वारा चेक के साथ चालान जमा करने के मामले में निम्नलिखित कार्रवाई करने की सूचना दी गई थी, जिसे धारा 44एबी के तहत क्षेत्रवार पैन और आने वाले करदाताओं के नाम वाली सीडी से सत्यापित किया जा सकता है।

ए) करदाता से अनुरोध है कि वह ई-भुगतान मोड के माध्यम से अपना भुगतान करें।

बी) यदि वह ऐसा करने में असमर्थता का दावा करता है, तो चेक को इस चेतावनी के साथ स्वीकार करें कि इसे अगले भुगतान के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा और वह अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

सी) शाखा में नेट बैंकिंग खाता खोलने के लिए करदाता की मदद करें।

डी) करदाताओं की जानकारी के लिए ई-भुगतान करने के लिए बैंकों को एक संक्षिप्त लेख और पालन किए जाने वाले चरण (अनुबंध IV के अनुसार) भी उपलब्ध किए गए थे।

27. प्रेषण की अनुमेय अवधि

ए) ई-भुगतान के माध्यम से प्राप्त ईएएसआईईएसटी और ओएलटीएएस सहित सभी सरकारी लेनदेन के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में प्रेषण अवधि टी + 1 कार्य दिवस (तिथि सहित), क्रमश: 1 अगस्त, 2008 और 1 नवंबर, 2010 से है, जहां "टी" वह दिन है जब प्राप्त बैंक शाखा के पास पैसा उपलब्ध होता है।।

1/5/2005 से 31/12/2006 की अवधि के दौरान लेनदेनों (राजस्व प्राप्तियों से संबंधित) के पुट थ्रू दिनांक को बाहर रखने की प्रयोज्यता उन मामलों के लिए जिनमें दंडात्मक ब्याज का पहले ही भुगतान किया गया हो :

अनुदेशों के अनुसार, सरकारी राजस्व के प्रेषण के लिए विलंबित अवधि ब्याज की गणना के लिए निर्धारित प्रेषण मानदंडों से 'पुट थ्रू डेट' को बाहर रखा गया था और ये अनुदेश विलंबित अवधि के ब्याज मामलों में लागू किया गया था जहां बैंकों ने ब्याज का भुगतान नहीं किया था। बैंकों द्वारा भुगतान किए गए दंडात्मक ब्याज के अतिरिक्त भुगतान को उनके विरुद्ध विलंबित अवधि के दंडात्मक ब्याज के बाद के दावों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा।

बी) सीमा शुल्क एवं सेवा कर की इलेक्ट्रॉनिक लेखा प्रणाली (ईएएसआईईएसटी) के तहत सरकारी खाते में सरकारी राजस्व को भेजने के लिए बाहरी लेनदेन के लिए टी + 5 कार्य दिवसों (पुट थ्रू डेट को छोड़कर) की अधिकतम अवधि की अनुमति दी जाएगी। यह व्यवस्था ई-भुगतान (इंटरनेट के माध्यम से किए गए भुगतान) पर लागू नहीं होगी, जिसके लिए क्रमशः 18 जुलाई, 2008 और 21 जनवरी, 2015 के आरबीआई/2008-09/97 और आरबीआई/2014-15/416 परिपत्रों के माध्यम से अलग-अलग निर्देश जारी किए गए हैं।

सी) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जम्मू और कश्मीर, लेह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पूर्वोत्तर क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा), झारखंड और छत्तीसगढ़ में स्थित शाखाओं के संबंध में सरकारी प्राप्तियों के सीएएस, आरबीआई, नागपुर को मैनुअल प्रेषण के

लिए के लिए 01.01.2010 से टी +12 कार्य दिवसों की अवधि (पुट थ्रू डेट को छोड़कर, जहां टी वह दिन है जब शाखा में धन उपलब्ध है) की अनुमति दी गई है।

वित्त मंत्रालय के निधि योजना अर्थात पीपीएफ़/ एससीएसएस आदि के तहत दूरस्थ, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में निधियों के विप्रेषण लागू नहीं होंगे।

28. सरकारी खातों में सरकारी प्राप्तियों के प्रेषण में देरी पर एजेंसी बैंकों से ब्याज की प्राप्ति

ए) डेबिट/ क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से सरकारी राजस्व के भुगतान के लिए एजेंसी बैंकों को निम्नलिखित अतिरिक्त मानदंडों का पालन करना आवश्यक है:

ई-पावती को सरकारी खाते में देरी से भेजे जाने पर दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा, अर्थात टी+1 कार्य दिवस से अधिक देरी पर, यदि कोई हो, और निपटान भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में निहित प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुरूप होना चाहिए।

बी) सरकारी प्राप्तियों के प्रेषण में देरी पर दंडात्मक ब्याज की छोटी राशि लगाना:

यह निर्णय लिया गया है कि 500/- रुपये या उससे कम की राशि वाले विलंबित अवधि दंडात्मक ब्याज के छोटे-मोटे दावों की अनदेखी की जाएगी और उन्हें 1 जनवरी 2008 से दण्डात्मक ब्याज के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

अनुबंध।

ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओएलटीएएस) से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया

---

1. प्राप्तकर्ता शाखाओं में करों की स्वीकृति की प्रक्रिया

1.1 करदाता अधिकृत बैंक की किसी भी अधिकृत शाखा में प्रत्यक्ष कर का भुगतान नकद, खाते में प्रत्यक्ष डेबिट या उसी बैंक या उसी केंद्र पर किसी अन्य बैंक/शाखा जहां भुगतान किया जाता है पर आहरित चेक/ड्राफ्ट द्वारा भुगतान कर सकता है,। बाहरी चेक/ड्राफ्ट द्वारा कर का भुगतान किसी अधिकृत बैंक में या प्राधिकृत बैंक/शाखा को विप्रेषण के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किया जा सकता है। प्रत्येक भुगतान के लिए निर्धारित प्रारूप में चालान होना चाहिए। चालान प्रारूप एक एकल प्रतिलिपि चालान है जिसमें मुख्य चालान शीर्ष पर है और करदाता का काउंटरफॉइल चालान के निचले भाग में है (अनुबंध 'ए' पर नमूना)।

1.2 प्राप्तकर्ता शाखा के काउंटर पर

भुगतान स्वीकार करते समय प्राप्तकर्ता शाखा के प्राप्तकर्ता क्लर्क/टेलर को निम्नलिखित बिंदुओं की जांच करनी होगी: –

ए) क्या चालान का मुख्य हिस्सा और करदाता के काउंटरफॉइल फॉर्म को ठीक से भरा गया है और जिस राशि और खाते के प्रमुख मद में राशि का हिसाब/जमा किया जाना है, उसे सही ढंग से दर्ज किया गया है;

बी) क्या स्थायी खाता संख्या (पैन) या कर कटौती खाता संख्या (टैन), करदाता का नाम और पता, आकलन वर्ष और भुगतान की प्रकृति और प्रकार का विवरण ठीक से भरा गया हो। राशि शब्दों और आंकड़ों दोनों में सही ढंग से लिखी जानी चाहिए।

सी) क्या निर्धारित स्थान पर चालान में स्थायी खाता संख्या (पैन)/ कर कटौती खाता संख्या (टैन) दिया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 139 ए (5) (बी) के तहत पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 203A के अंतर्गत टैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। करदाता द्वारा उद्धृत इस संख्या को मान्य किया जाना चाहिए (यह देखने के लिए जांच की जानी चाहिए कि क्या यह वैध पैन / टैन संरचना के अनुरूप है) और कर भुगतान स्वीकार करने वाले विनिर्दिष्ट बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भुगतान के लिए चालान केवल तभी स्वीकार किए जाते हैं जब चालान में एक वैध पैन का उल्लेख किया जाता है। हालांकि, जहां करदाता इंगित करता है कि उसने पहले ही पैन या टैन के आवंटन के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक इसे आवंटित नहीं किया है, तो बैंक द्वारा कर भुगतान चालान स्वीकार किए जा सकते हैं बशर्ते करदाता पैन / टैन आवेदन संख्या चालान में इंगित करता है। ऐसे मामलों में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि **चालान में करदाता के पूरे पते का उल्लेख किया गया है।**

1.3 चालान की जांच करने और खुद को संतुष्ट करने के बाद कि नकद, चेक या ड्राफ्ट की राशि चालान में दिखाई गई राशि से मेल खाती है, और यह भी कि चेक पोस्ट डेटेड / पुराना नहीं है, शाखा के रिसीविंग टेलर या काउंटर-क्लर्क निविदाकर्ता को एक पेपर टोकन जारी करेंगे ताकि उसे काउंटरफॉइल रसीद की डिलीवरी की सुविधा मिल सके। अन्य बैंक शाखाओं में निकाले गए चेक या ड्राफ्ट के साथ जमा किए गए चालान के मामले में, काउंटरफॉइल रसीद केवल चेक या ड्राफ्ट की राशि की प्राप्ति पर जारी की जाएगी और इसलिए पेपर टोकन को उस तारीख को वहन करना चाहिए जिस दिन यह उपलब्ध होगा।

1.3.1 नकद के साथ प्रस्तुत किए गए चालान

जांच के बाद यदि नकद के साथ चालान दिया जाता है, तो उस पर 'कैश रिसीव' लिखा होगा। बैंक चालान के मुख्य हिस्से और करदाता के काउंटरफॉइल दोनों पर बैंक और शाखा के नाम, शाखा के बीएसआर कोड (7 अंक), राशि की जमा की तारीख (डीडीएमएमवाईवाई) और चालान का अद्वितीय सीरियल नंबर (5 अंक) भी स्टांप करेगा। स्टाम्प मुख्य भाग के साथ-साथ चालान के करदाता के काउंटरफॉइल दोनों पर लगाया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि रसीद स्टाम्प की छाप स्पष्ट और पठनीय हो।

शाखा का एक अधिकृत अधिकारी चालान के करदाता के काउंटरफॉइल पर पूर्ण हस्ताक्षर करेगा और राशि प्राप्त करने वाले चालान की मुख्य प्रति पर आद्य हस्ताक्षर। करदाता के काउंटरफॉइल में, प्राप्त राशि को शब्दों और संख्या दोनों में इंगित किया जाएगा। प्राप्त करदाता का काउंटरफॉइल निविदाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और उसके बाद मुख्य प्रति रसीद स्क्रॉल में स्क्रॉल करने के लिए पारित की जाएगी।

1.3.2 चेक/ड्राफ्ट के साथ दिए गए चालान

चेक/ड्राफ्ट के साथ दिए गए चालान पर 'डबल डेट स्टैम्प' लगाया जाएगा ताकि लिखत की निविदा की तारीख के साथ-साथ उसकी प्राप्ति की तारीख भी दर्शायी जा सके। यह संभव हो सकता है कि कुछ शाखाएं चालान काउंटर पर चालान जारी होते ही चालान पर इनवर्ड स्टांप लगाने की परंपरा का पालन कर रही हों। यद्यपि, उस स्थिति में डबल डेट स्टैम्प आवश्यक नहीं हो सकता है। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चालान की मुख्य प्रति और करदाता के काउंटरफॉइल दोनों पर आवक तिथि स्टाम्प हमेशा लगे हो।

चेकिंग अधिकारी शुरू में यह सुनिश्चित करेगा कि चेक/ड्राफ्ट की राशि और निविदाकर्ता द्वारा चालान में दर्ज राशि के बीच कोई अंतर नहीं है। इसके बाद चेक/ड्राफ्ट को वसूली के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद, चेक/ड्राफ्ट की **वसूली पर, वसूली की तारीख डबल डेट स्टैम्प पर या चालान में स्थान में इंगित की जाएगी, जैसा भी मामला हो।** बैंक एकल कॉपी चालान के मुख्य और करदाता दोनों के काउंटरफॉइल पर बैंक और शाखा के नाम, शाखा के बीएसआर कोड (7 अंक) राशि की जमा तिथि (डीडीएमएमवाईवाई) और चालान के अद्वितीय सीरियल नंबर (5 अंक) का उल्लेख करने वाले एक स्टाम्प के साथ मुहर लगाएगा। राशि प्राप्त करने के लिए चालान काटने के बाद, करदाता का काउंटरफॉइल टोकन छोड़ने के विरुद्ध निविदाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा।

1.3.3 चालान का संख्याकन

प्रत्येक दिन के लिए सभी चालान (नकद और चेक द्वारा भुगतान दोनों) के लिए क्रियाशील क्रम संख्या दिया **जाएगा।** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी विशेष दिन जारी किए गए प्रत्येक चालान पर क्रम संख्या बाद में इसका पता लगाने के लिए **अद्वितीय** होना चाहिए। **इसलिए बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए** कि नकद के साथ **जमा किए गए चालानों को दिए गए क्रम संख्या उन चालानों को दिए गए क्रम संख्या के साथ ओवरलैप न हों, जिनके विरुद्ध उस दिन चेक प्राप्त किए गए हैं।**

उसी शाखा में देय नकद और चेक/ड्राफ्ट के साथ दिए गए चालानों का काउंटरफॉइल काउंटर पर विधिवत प्राप्त निविदाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा। एक ही बैंक की अलग-अलग शाखा या उसी केंद्र पर स्थित किसी अन्य बैंक की चेक/ड्राफ्ट के साथ दिए गए चालान, के लिए करदाता के काउंटरफॉइल को किसी भी दिन के क्लियरिंग के अवैतनिक दस्तावेजों की वापसी के लिए 'लोकल बैंकर्स क्लियरिंग हाउस' के नियमों के तहत निर्धारित कार्य दिवस के पहले विधिवत प्राप्ति के साथ लोटना चाहिए।

1.4.1 ड्राफ्ट के साथ दिए गए चालान के मामले में, चेक की वसूली की तारीख चालान के मुख्य भाग पर भी मुहर लगाई जाएगी, जिसे रसीद स्क्रॉल के साथ जोनल लेखा कार्यालय (जेडएओ) को आगे के प्रसारण के लिए बैंक में रखा जाएगा। हालांकि आयकर अधिनियम के अनुसार चेक/डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की तारीख को कर के भुगतान की तारीख माना जाएगा, लेकिन चेक/ डिमांड ड्राफ्ट को प्राप्ति के बाद ही स्क्रॉल किया जाएगा।

1.4.2 प्राप्त चालान पर दोहरी तिथि

चालान का मुख्य भाग जिसके माध्यम से चेक / ड्राफ्ट जमा किया जाता है, इसलिए, निम्नानुसार दो तिथियां होंगी:

i) जमा तिथि : DDMMYY (रबर स्टाम्प पावती में)

ii) प्राप्ति की तिथि : DDMMYY (चालान में इंगित स्थान पर)

नकद जमा के मामले में जमा की तिथि और प्राप्ति की तारीख समान होगी।

1.4.3 संग्राहक बैंक किसी अन्य प्रारूप में पावती जारी नहीं करेगा।

2. संग्राहक बैंक द्वारा स्क्रॉल की तैयारी

2.1 प्रत्येक दिन बैंक शाखा काउंटर पर प्राप्त सभी चालानों को एक रनिंग सीरियल नंबर दिया जाएगा, जिसके विरुद्ध नकद भुगतान किया गया है या उस तारीख को चेक / ड्राफ्ट वसूल किए गए हैं।

2.2 बैंक काउंटर पर करदाता द्वारा चालान जमा किए जाने पर शाखा के नाम और पैन, सीरियल नंबर, जमा की तारीख और बीएसआर कोड जैसे सभी चालान फ़ील्ड को कैप्चर करना आवश्यक है। जैसा आयकर विभाग द्वारा बैंकों को सूचित किया जाए, उसी अनुसार चालान के क्षेत्रों की डेटा संरचना को कैप्चर और प्रेषित किया जाना है। स्थायी खाता संख्या (पैन) और करदाता का नाम हमेशा रसीद और भुगतान स्क्रॉल में शामिल किया जाएगा।

2.3 ग्राहक बैंकिंग कार्य काल के अंत में, बैंक शाखा को उन सभी चालानों की पहचान करनी चाहिए जिनके विरुद्ध उस दिन के लिए नकद में भुगतान प्राप्त किया गया है या जिनके लिए उस दिन के लिए चेक / ड्राफ्ट द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया है। चूंकि इन सभी चालानों का विवरण पहले से ही बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में है, इसलिए शाखा को उस दिन के लिए भुगतान किए गए सभी चालान डेटा वाली एक फाइल तैयार करनी चाहिए और इसे आयकर विभाग के टिन और बैंकों के लिंक सेल को आगे ट्रांसमिशन के लिए अपनी नोडल शाखा को प्रेषित करना चाहिए। **तथापि, गैर-कम्प्यूटरीकृत/गैर-नेटवर्ककृत प्राधिकृत शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी निकटतम कम्प्यूटरीकृत/नेटवर्क शाखा से डाटा नोडल शाखा को प्रेषित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उस दिन जिस चालान का भुगतान किया गया है, उसे छोड़ा न जाए। एक वित्तीय**

वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के लिए एक रनिंग स्क्रॉल सीरियल नंबर प्रत्येक प्रकार के कर (प्रमुख शीर्ष), जो किसी विशेष दिन प्रेषित किए जाते हैं, से संबंधित रिकॉर्ड को दिया जाएगा। रिकॉर्ड की डेटा संरचना और बैंक द्वारा विभाग को प्रेषित की जाने वाली फाइल आयकर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में होगी। **आयकर विभाग को प्रेषित किए जाने के बाद संग्रह शाखा किसी भी मामले में ऑनलाइन डेटा फ़ाइल को अपनी ओर से नहीं बदलेगी।**

2.4 लौटाये गए समाशोधन पर कार्यवाही

संग्रहण शाखा को उन सभी चालानों की भी पहचान करनी चाहिए जिनके विरुद्ध लिखतों को अदत्त वापस कर दिया गया था। संबंधित चालान के साथ ऐसे लिखतों को बैंक में अलग से रखा जाना चाहिए ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

2.5 संग्रहण शाखा अपने कंप्यूटर पर आयकर विभाग को प्रसारित किए गए चालान डेटा से दैनिक आधार पर कर के प्रकार में सारांश ..... में स्क्रॉल और फॉर्म ..... के आधार पर फॉर्म (वार-प्रमुख शीर्ष) के अलगअलग प्रिंटआउट भी तैयार करेगी।- एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में लागू रनिंग सीरियल नंबर जिसके आगे संबंधित कर के प्रकार (प्रमुख शीर्ष) का संक्षिप्त नाम लगा हो, और जिसे संबंधित दिन के लिए प्रेषित स्क्रॉल पर मुद्रित किया गया था, को स्क्रॉल पर मुद्रित किया जाएगा। संग्रहण शाखा किसी भी स्थिति में उस डेटा से कोई मुद्रित स्क्रॉल या सारांश उत्पन्न नहीं करेगी जो विभाग को पहले प्रेषित डेटा से किसी भी तरह से बदला गया हो।। इस प्रकार शाखा द्वारा उत्पन्न स्क्रॉल बैंक द्वारा विभाग के टिन को ऑनलाइन प्रेषित डेटा से आरसीसी द्वारा उत्पन्न स्क्रॉल से बिल्कुल मेल खाएंगे। इसके बाद, शाखा कंप्यूटर मुद्रित सारांश और रसीदों का एक सेट तैयार करेगी और प्रत्येक स्क्रॉल के साथ **भौतिक चालान को उसी क्रम में व्यवस्थित करेगी जिसमें उन्हें स्क्रॉल में दर्ज किया जाता है।** अगले कार्य दिवस की शुरुआत में, प्राप्तकर्ता शाखा **इसे जेडएओ** को आगे के प्रसारण के लिए नोडल शाखा को अग्रेषित करेगी **।**

2.6 त्रुटि रिकॉर्ड का संचरण

करदाता द्वारा किए गए भुगतान की राशि या भुगतान के प्रमुख शीर्ष की रिपोर्ट करने में संग्रहणकर्ता बैंक शाखा द्वारा किसी भी त्रुटि के मामले में**,** बैंक एक त्रुटि रिकॉर्ड के माध्यम से टिन को ऑनलाइन सही जानकारी प्रेषित करेगा**,** जिसके लिए प्रारूप आयकर विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। राशि और खाते के प्रमुख में त्रुटियों के सुधार को नोडल शाखा के माध्यम से भेजे जाने वाले 'त्रुटि स्क्रॉल' के माध्यम से जेडएओ को भी सूचित किया जाएगा। बैंक द्वारा टिन को दी गई कर भुगतान की राशि ही आयकर विभाग द्वारा करदाता द्वारा किए गए भुगतान के रूप में स्वीकार की जाएगी।

3. आयकर रिफंड आदेश (आईटीआरओ)/ईसीएस के भुगतान की प्रक्रिया

3.1 प्रत्यक्ष कर वापसी का कार्य अधिकृत बैंक की एक आईटीडी केंद्र / एक जिले में केवल एक शाखा को सौंपा जाता है, जिसमें आम तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहयोगी बैंक होते हैं। रिफंड आदेश करदाता द्वारा उसी शाखा के साथ अपने खाते में हस्तांतरण के लिए शाखा में प्रस्तुत किए जाएंगे। वैकल्पिक रूप से, इसे समाशोधन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। रिफंड ऑर्डर लेने के लिए अधिकृत आयकर विभाग के अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर आयकर प्राधिकरियों द्वारा संबंधित भुगतान करने वाली शाखाओं को अग्रिम रूप से भेजे जाएंगे। नमूना हस्ताक्षर आयकर विभाग के एक अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा, जिसका नमूना हस्ताक्षर पहले से ही शाखा के साथ रिकॉर्ड के तौर पर है। अधिकृत अधिकारी में किसी भी बदलाव की सलाह तुरंत संबंधित शाखा को दी जाएगी। कार्यमुक्त अधिकारी कार्यमुक्त अधिकारी के हस्ताक्षर का नमूना सत्यापित करेगा।। भुगतान के लिए रिफंड आदेश पारित करते समय, पासिंग अधिकारी को परक्राम्य लिखत के भुगतान के संबंध में बैंकों द्वारा

आमतौर पर बरती जाने वाली सावधानियों, महालेखा नियंत्रक के साथ-साथ रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अलावा अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। भुगतानकर्ता को आयकर रिफंड ऑर्डर (आईटीआरओ) के पीछे 'दावेदारों के हस्ताक्षर' के लिए प्रदान की गई जगह में अपना हस्ताक्षर करना आवश्यक है। रिफंड सलाह से संबंधित प्रक्रिया वर्तमान में जारी रहेगी, सिवाय इसके कि भुगतान किए गए आईटीआरओ और मुद्रित भुगतान स्क्रॉल की सलाह अब बैंक द्वारा आयकर विभाग को नहीं भेजी जाएगी।

3.2 जैसा कि प्राप्तियों के मामले में होता है, रिफंड को भुगतानकर्ता शाखा द्वारा कर के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है जिसके तहत रिफंड किया जाता है।। आईटीआरओ के भुगतान के संबंध में अलग से प्रमुख शीर्ष वार भुगतान रिकॉर्ड बनाए जाएंगे।

3.3 प्रत्यक्ष कर रिफंड भी आरबीआई की इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस स्कीम (ईसीएस) के माध्यम से सीधे करदाता के बैंक खाते में जमा किया जा सकता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, करदाता अपने आय रिटर्न में अपने बैंक खाते (बचत या चालू), खाता संख्या और बैंक शाखा कोड (9 अंक) के प्रकार का उल्लेख करके एक अध्यादेश देता है। करदाता के रिटर्न की प्रोसेसिंग और आकलन अधिकारी द्वारा रिफंड के निर्धारण के बाद, आरसीसी के अधिकार क्षेत्र में सभी करदाता के रिफंड (जिसमें ईसीएस के माध्यम से क्रेडिट मांगा गया है) स्वचालित रूप से आरसीसी में कंप्यूटर सिस्टम पर समेकित हो जाते हैं। यह सभी रिफ़ंड डेटा डाउनलोड, एन्क्रिप्ट किया जाता है और चुंबकीय मीडिया (फ्लॉपी या पुनर्लेखन योग्य सीडी) पर कॉपी किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है। यह आरसीसी द्वारा स्थानीय जेडएओ के साथ-साथ आरबीआई या एसबीआई की रिफंड जारी करने वाली शाखा को भेजा जाता है। फाइल में डेटा को सत्यापित करने के बाद, बैंक रिफंड की कुल राशि के लिए आयकर विभाग के खाते को डेबिट करता है और उसके बाद बैंकों की विभिन्न स्थानीय शाखाओं को समाशोधन के माध्यम से निर्देश जारी करता है, जहां करदाता के खाते स्थित हैं ताकि विभाग द्वारा सूचित राशि के साथ करदाता के खातों को जमा किया जा सके। विभाग के खाते में यह एकल डेबिट उस दिन के लिए बैंक द्वारा आयकर विभाग को प्रेषित भुगतान (रिफंड) डेटा में दिखाई देता है। यदि खाता बंद होने आदि जैसे कारणों से करदाता के खातों में इनमें से कोई भी क्रेडिट प्रभावी नहीं होता है, तो बाद में आयकर विभाग के खाते में ईसीएस रिटर्न के लिए एक अलग माइनस डेबिट प्रविष्टि द्वारा इसका हिसाब लगाया जाता है और उस विशेष दिन के लिए प्रेषित भुगतान (रिफंड) डेटा के माध्यम से आयकर विभाग को सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (फ्लॉपी या पुनर्लेखन योग्य सीडी आदि) में फाइलें कंप्यूटर मुद्रित भुगतान (रिफंड) स्क्रॉल के साथ जेडएओ को वापस कर दी जाती हैं, जबकि वही डेटा बैंक द्वारा आयकर विभाग के कर सूचना नेटवर्क (टिन) के माध्यम से आयकर विभाग को ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है।

4. भुगतान की तैयारी (रिफ़ंड) स्क्रॉल

4.1 भुगतान स्क्रॉल तैयार करने की प्रक्रिया रसीद स्क्रॉल पर लागू प्रक्रिया के समान होगी।

4.2 स्क्रॉल को रसीदों से संबंधित सेट के समान सेट में बनाया जाएगा, सिवाय इसके कि चालान के बजाय, भुगतान किए गए रिफंड ऑर्डर स्क्रॉल के साथ होंगे। भुगतान किए गए रिफंड वाउचर के बारे में पूरा डेटा भुगतान करने वाले बैंक द्वारा विभाग के टिन में आगे के प्रसारण के लिए लिंक सेल को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाएगा, जबकि भुगतान किए गए रिफंड ऑर्डर के साथ भौतिक स्क्रॉल नोडल शाखा के माध्यम से जेडएओ को अग्रेषित किए जाएंगे। यदि नोडल शाखा स्थानीय रूप से स्थित नहीं है, तो उपरोक्त सभी दस्तावेज (रसीद / भुगतान स्क्रॉल आदि) अनिवार्य रूप से पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने चाहिए।

4.3 ईसीएस रिफंड के मामले में, डेटा लिंक सेल और बाद में आयकर विभाग को ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वही ईसीएस विवरण नोडल शाखा के माध्यम से भुगतान बैंक द्वारा स्थानीय जेडएओ को भेजा जाएगा।

5. करदाता द्वारा काउंटरफॉइल को खो देना

जमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त चालान काउंटरफॉइल को खो देने की स्थिति में, बैंक शाखाएं करदाताओं से क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लिखित में एक विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर, प्रत्येक मामले में आवेदक की प्रमाणिकता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद जमाकर्ता को उनके रिकॉर्ड के आधार पर जारी कर सकती हैं और अपने विवेक पर मामूली शुल्क ले सकती हैं। प्रमाण पत्र में चालान विवरण अर्थात राशि, बैंक का नाम और शाखा, बीएसआर कोड और चेक / नकद जमा करने की तारीख, प्रमुख शीर्ष, चालान क्रम संख्या, चेक की प्राप्ति की तारीख / नकद जमा करने की तारीख और एकत्र करने वाली शाखा स्क्रॉल नंबर और तारीख जिस पर कर भुगतान का विवरण पहले प्रेषित किया गया है, का उल्लेख होना चाहिए।

6. नोडल शाखा का कार्य

6.1 नोडल शाखा त्विरत एवं सटीक प्रेषण, अपने क्षेत्र अधिकार मेंआने वाली सभी प्राप्तकर्ता शाखाओं द्वारा प्रतिदिन उसे रिपोर्ट की गयी वसूलियों /धन-वापसी (अपनी स्वयं की प्राप्तियों सहित) की अकाउंटिंग के लिए उत्तरदायी होगी। वह अपने से संबद्ध सभी प्राप्त कर्ता शाखाओं की वसिलू यों (अपनी स्वयं की वसूलियों सहित) को आरबीआई, सीएएस, नागपुर में मौजूद सरकारी लेखा को तत्परता के साथ भेजने के लिए भी ज़िम्मेवार होगी। वह आंचिलक लेखा कार्यालयों के साथ आंकड़ों के समाधान के लिए भी जिम्मेदार होगी।

6.2 वसूली कर्ता शाखाओं से किसी दिन विशेष को प्राप्त किए गए सभी चालानों के संबंध में ऑन-लाइन डेटा प्राप्त होने पर, नोडल शाखा दैनिक आधार पर निम्नलिखित कार्रवाई करेगी:

ए) वह चालान के आांकड़ों को अपनी कांतयूटर प्रणाली पर मिलाएगी तथा उस दिन भेजे जाने वाले सभी चालान रिकार्डों को एक कॉमन नोडल शाखा स्क्रोल नंबर तथा तारीख देते हुए आांकड़ों को आयकर विभाग के कर सूचना नेटवर्क को आगे भेजने हेतु उसी दिन आयकर विभाग द्वारा निर्धारित फॉमेट में अपने लिंक सेल को भेज देगी।

बी) वह कंप्यूटर के आांकड़ों के आधार पर एक फ्लॉपी में अथवा अन्य मीडिया में (आंचलिक लेखा कायातलय द्वारा यथा सूचित) साराांश की एक प्रति तथा मुख्य स्क्रोल भी तैयार करेगी एवं उन्हें अगले कार्य दिवस पर आंचलिक लेखा कार्यालय को भेज देगी।

सी) संग्रहकर्ता शाखा से कंप्यूटर जनित शाखा स्क्रॉल की हार्ड कॉपी प्राप्त होने पर, नोडल शाखा यह सत्यापित करेगी कि ये कंप्यूटर-जेनरेटेड शाखा स्क्रॉल पहले वसूलिकर्ता शाखाओं द्वारा भेजे गए आंकड़ों से पूरी तरह मेल खाते हैं। वह प्रमुख शीर्षवार सभी स्क्रॉल को एक साथ जोड़ते हुए प्रमुख स्क्रोल के साथ अपने प्रमुख के आंकड़ों सहित सभी शाखाओं से प्राप्त इन कंप्यूटर मुद्रित शाखा स्क्रॉल (चालान के साथ) को समेकित करेंगी। यह प्रमुख शीर्ष -वार मुख्य स्क्रॉल और सारांश का एक कंप्यूटर प्रिंटआउट भी तैयार करेंगी। तब वह इन्हें दैनिक आधार पर संबंधित जेडएओ को भेजेंगी।

डी) उपर्युक्त में चर्चा के अनुसार चालान रहित उसी तरीके से तैयार स्क्रॉल का दूसरा सेट नोडल शाखा अपने रिकॉर्ड के लिए रखेंगी।

ई) नोडल शाखा उसी प्रकार से, भुगतानों (अर्थात धन वापसी) के लिए भी कंप्यूटर मुद्रित अलग मुख्य स्क्रॉल भी तैयार करेगी और उन्हें भुगतान किए गए आईटीआरओ के साथ जेडएओ को अग्रेषित करेगी। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ईसीएस रिफंड विवरण स्थानीय जेडएओ को भी अग्रेषित करेगा। रिफंड डेटा (पेपर आईटीआरओ और ईसीएस रिफंड के संबंध में) नोडल शाखा द्वारा लिंक सेल के माध्यम से टिन को ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा। यह भुगतान किए गए आईटीआरओ की सूचना को बनाए रखेगा।

एफ) प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम पंद्रह दिनों के दौरान, नोडल शाखाएं स्क्रॉल के दो अलग-अलग सेट तैयार करेंगी और भेजेगी - एक अप्रैल लेनदेन से संबंधित सामान्य स्क्रॉल और दूसरा मार्च लेनदेन से संबंधित (जिसका अर्थ है कि प्राप्तकर्ता शाखाओं द्वारा 31 मार्च तक प्रस्तुत और 31 मार्च के बाद लेकिन 15 अप्रैल से पहले नोडल शाखा को भेजे गए चेक/ ड्राफ्ट/ आईटीआरओ के स्क्रॉल)। ये नोडल शाखा द्वारा मार्च अवशिष्ट लेखा के रूप में सूचीबद्ध किए जाएँगे। नोडल शाखाएं इन लेनदेन को मार्च लेनदेन के रूप में शामिल करने के लिए नागपुर में लिंक सेल को सूचित करेंगी। नोडल शाखाएं प्रमुख रूप से लेखा का माह दर्शाते हुए अप्रैल लेन देन के लिए एक और स्क्रॉल भेजेंगी। 31 मार्च को या उससे पहले दिए गए किसी भी चेक/ड्राफ्ट जिसका भुगतान अप्रैल में हुआ है उसको अप्रैल के लेनदेन में माना जाएगा। हालांकि, इस अनुदेश को ध्यान में रखते हुए उन सभी चालानों के आंकड़े उसी दिन ऑनलाइन पर आयकर विभाग को प्रेषित किया जाना चाहिए, जिनका भुगतान संबन्धित दिन पर प्राप्त हो चुका है, असाधारण मामलों में ही अलग मार्च अवशिष्ट स्क्रॉल की आवश्यकता होनी चाहिए।

जी) नोडल शाखा अपने द्वारा दी गई समेकित राशि को अपने लिंक सेल को दिन-प्रतिदिन के आधार पर हस्तांतरित करेगी।

7. **कर संग्रहण को सरकारी खाते में जमा करना**

7.1 नोडल शाखा अपने नियंत्रण में आने वाली सभी प्राप्तकर्ता शाखाओं के लिए एक पूलिंग केंद्र के रूप में कार्य करती है और यह जेडएओ को लेनदेन (सभी संबंधित दस्तावेजों यानी चालान और स्क्रॉल के साथ) की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। यह इन सभी लेनदेन के लिए चालान डेटा को नागपुर में अपने लिंक सेल को प्रेषित करने के लिए भी जिम्मेदार है ताकि आयकर विभाग को ऑनलाइन ट्रांसमिशन किया जा सके और साथ ही प्राप्तकर्ता राशि को भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में जमा किया जा सके।

7.2 नोडल शाखा एक दैनिक ज्ञापन तैयार करेगी और इसे दैनिक आधार पर नागपुर में अपने लिंक सेल (एसबीआई के मामले में जीएडी, मुंबई) को भेजेगी, जो उसके आधार पर आरबीआई, सीएएस, नागपुर के साथ दैनिक निपटान करेगा।

7.3 नागपुर स्थित बैंकों का लिंक सेल आयकर विभाग के कर सूचना नेटवर्क (टिन) को प्रेषित करने के लिए नोडल शाखा से प्राप्त चालान डेटा को समेकित करेगा और वह नोडल शाखाओं से प्राप्त होने वाली दैनिक प्राप्तियों की निगरानी तथा दैनिक मेमो की सटीकता की भी जांच करेगा। इसके बाद लिंक सेल दैनिक ज्ञापन सीएएस, आरबीआई, नागपुर को भेजेगा।

7.4 बैंकों की नोडल शाखाएं नागपुर स्थित अपने लिंक सेल के साथ उनके द्वारा निपटान की गई राशि का जेडएओ के साथ मासिक समाधान करेंगी। जेडएओ अपने रिकॉर्ड के आधार पर नोडल शाखाओं से प्राप्त विवरणों को प्रमुख शीर्ष -वार और नोडल बैंक-वार दोनों ही आधार पर सत्यापन करेंगे। किसी भी विसंगति के मामले में, नोडल शाखा तुरंत सुधार करेगी और जेडएओ को सूचना के तहत नागपुर में अपने लिंक सेल के माध्यम से सीबीडीटी के खाते में पहले से जमा / डेबिट की गई राशि में अंतर को समायोजित करेगी।

7.5 जेडएओ और लिंक सेल के साथ लेनदेन के अंतिम समाधान के उद्देश्य से, सीएएस, आरबीआई, नागपुर एक मासिक विवरण तैयार करेगा और इसे जेडएओ और बैंकों के लिंक सेल को प्रस्तुत करेगा। आरबीआई, सीएएस नागपुर अगले महीने के 20 तारीख तक एक मासिक विश्लेषण सीसीए, सीबीडीटी को प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रमुख हेड-वार प्राप्तियों / रिफंड आदि को दर्शाता है।

8. कर संग्रहण के विप्रेषण की अवधि और दंडात्मक ब्याज लगाने की अवधि

8.1 प्राधिकृत बैंकों की नामित शाखाओं द्वारा किए गए कर संग्रह को दैनिक आधार पर तुरंत सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए। एजेंसी बैंकों द्वारा सीएएस, नागपुर में सरकारी खाते में कर संग्रह भेजने के लिए अनुमत अधिकतम दिनों की संख्या निम्नानुसार है:

<table>
<tr><th>माध्यम</th><th colspan="2">सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए धनप्रेषण अवधि</th><th>निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए धनप्रेषण अवधि</th></tr>
<tr><td>भौतिक</td><td><u>स्थानीय लेनदेन</u>
टी + 3 कार्य दिवस
(पुट थ्रू तिथि को छोड़कर)</td><td><u>बाहरी लेनदेन</u>
टी + 5 कार्य दिवस (पुट-थ्रू तिथि को छोड़कर)</td><td>टी + 3 दिन
(पुट-थ्रू तिथि,
रविवार और छूटियों सहित)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">दूरस्थ, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए
टी + 12 कार्य दिवस
(पुट-थ्रू तिथि को छोड़कर)</td><td></td></tr>
<tr><td>ई-भुगतान</td><td colspan="2">टी +1 कार्य दिवस
(पुट-थ्रू तिथि सहित)</td><td>टी + 1 कार्य दिवस
(पुट-थ्रू तिथि सहित)</td></tr>
</table>

8.2 यदि उपर्युक्त निर्धारित अवधि से अधिक कोई विलंब होता है, तो बैंक विलंबित अवधि के लिए ब्याज देने के लिए उत्तरदायी हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आंचलिक लेखा कार्यालयों द्वारा विलंबित विप्रेषण के लिए ब्याज को निर्धारित किया जाना होगा और चूककर्ता बैंक से वसूल किया जाना होगा। वसूल की जानेवाली ब्याज की दर, प्रचलित बैंक दर + 2 प्रतिशत अथवा समय-समय पर सीजीए के साथ परामर्श करके रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अनुसार होगी।

9. "मार्च" लेनदेन का लेखांकन

9.1 रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में मार्च के लेनदेन के लेखा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में प्रत्यक्ष कर एकत्र करने वाले सभी बैंकों को विशेष निर्देश जारी करेगा।

9.2 नोडल बैंकों को चालू वर्ष के अप्रैल में पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च से संबंधित स्क्रोल प्राप्त होंगी। उसी वित्तीय वर्ष में मार्च की सम्पूर्ण वसूलियों के लेखांकन की दृष्टि से, नोडल बैंकों को अप्रैल के महीने में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा :

नोडल बैंकों को अलग-अलग स्क्रॉल के दो सेट तैयार करने होंगे - एक मार्च अवशिष्ट वसूलियों (31 मार्च से पहले करदाता के खाते से वसूल हुआ भुगतान) और दूसरा अप्रैल में पहले 15 दिनों के दौरान अप्रैल लेनदेनों के लिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राप्तकर्ता शाखाओं द्वारा 31 मार्च तक प्राप्त समस्त कर-वसूलियों को "मार्च अवशिष्ट लेनदेनों" के रूप में हिसाब में ले लिया जाता हैऔर उन्हें वित्तीय वर्ष में आने वाले अप्रैल के लेनदनों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। 1 से 15 अप्रैल तक तैयार किए गए मार्च लेनदेन के लिए मुख्य स्क्रॉल को स्पष्ट रूप से **"मार्च अवशिष्ट"** के रूप में चिह्नित किया जाना है।

9.3 यह भी नोट किया जाना चाहिए कि 31 मार्च को या उससे पहले प्राप्त किए गए सभी चेक/ वसूल हुई राशि को को चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित लेन-देन माना जाना चाहिए और चालू वित्त वर्ष में **"मार्च या मार्च अवशिष्ट लेनदेन"** शीर्षक के अंतर्गत इस प्रकार का हिसाब रखा जाना चाहिए।

9.4 नोडल बैंकों को नागपुर स्थित अपने लिंक सेल को रिपोर्टिंग करते समय आंकणों के दो सेट भेजने चाहिए जिन पर अलग-अलग स्पष्ट रूप से 15 अप्रैल तक के **मार्च अवशिष्ट** और अप्रैल लेनदेन दर्शाया जाए।

9.5 तिथि-वार मासिक विवरण भी दो सेटों में तैयार किए जाने चाहिए, एक **मार्च अवशिष्ट लेनदेनों** से संबंधित और दूसरा **अप्रैल लेनदेनों** से संबंधित।

10. प्रतिवर्ष मार्च के महीने के दौरान विशेष व्यवस्था

शाखाओं को पहले पैराग्राफ में बताई गई प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्यक्ष करों के लिए की गई वसूलियाँ नोडल शाखा / लिंक सेल के माध्यम से सरकारी खाते में जमा करने के लिए तुरंत भेज दी जायें। तथापि, मार्च के दूसरे पखवाड़े के दौरान, जहां भी प्राप्तकर्ता शाखाएं और नोडल शाखा स्थानीय रूप से अवस्थित हैं, प्राप्तकर्ता शाखाओं द्वारा एक विशेष संदेशवाहक प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। प्रत्येक वर्ष जून, सितम्बर और दिसम्बर के दूसरे पखवाड़े के दौरान दैनिक आधार पर आंचलिक लेखा कार्यालय को वसूली आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए भी सभी प्रयास किए जाएं ताकि वे आंकड़े निगरानी, अनुमान आदि के लिए आगे सरकार को भेजे जा सकें।

11. निगरानी समिति - आवधिक बैठकों का आयोजन

प्राधिकृत बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष करों के संग्रहण और लेखांकन के लिए संशोधित योजना के सुचारू संचालन के लिए निगरानी समितियों का प्रत्येक आंचलिकलेखा कार्यालय केंद्र पर गठन किया जाएगा जिसमें नोडल बैंकों/ बैंकों के स्थानीय प्राधिकरणों, आंचलिक लेखा कार्यालयों और आयकर विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। उक्त समिति छमाही बैठक करेगी और प्रत्यक्ष कर कार्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे लेखा, स्क्रॉलिंग, रिपोर्टिंग, विप्रेषण और समाधान आदि पर चर्चा करेगी और अपने स्तर पर समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास करेगी। इसके अलावा, वार्षिक आधार पर एक विशेष निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें सीबीडीटी, आरबीआई, आयकर विभाग और बैंकों के अति वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे और इस क्षेत्र में बैंकों, आंचलिक लेखा कार्यालयों और आयकर विभाग के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का निवारण करेंगे। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।

12. जनता की शिकायतों का निवारण

प्रत्येक प्राधिकृत बैंक के पास समय-समय पर निर्धारित सरकारी विभागों या जनता के सदस्यों को सेवा प्रदान करने वाली शाखाओं में सार्वजनिक शिकायतों से निपटने के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया होनी चाहिए। यदि बैंक को कर भुगतान की रिपोर्ट करने में त्रुटि का पता चलता है या कर भुगतान के प्रमुख शीर्ष में कोई त्रुटि देखता है चाहे वह स्वत: संज्ञान में आती है या करदाता द्वारा उसके ध्यान में लायी जाता है, तो बैंक तुरंत त्रुटि रिकॉर्ड (जैसा कि पैरा 2.6 और 7.4 में पहले वर्णित है) को टिन को प्रेषित करेगा। यह आदेशात्मक है क्योंकि आयकर विभाग बैंक द्वारा टिन को प्रेषित जानकारी पर ही करदाता के खाते में राशि जमा करेगा।

अनुबंध II

ओएलटीएएस

फ़ाइल पृथक्करण सुविधा(एफ़एसयू) के लिए यूज़रमैनुअल

प्रस्तावना

बैंकों द्वारा एफएसयू का उपयोग अमान्य इनपुट फ़ाइल और संबंधित त्रुटि फ़ाइल से एक वैध फ़ाइल उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। यह उपयोगकर्ता मैनुअल बैंक उपयोगकर्ताओं को इस फ़ाइल पृथक्करण सुविधा में प्रदान की गई कार्यक्षमताओं को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम करेगा।

भावी उपयोगकर्ता:

यह मैनुअल ओएलटीएएस में भाग लेने वाले बैंकों के लिंक सेल के लिए है।

उपयोग में लायी गई परिपाटी

प्रत्येक कार्य के बाद फ़ील्ड विवरण तालिका में प्रत्येक फ़ील्ड या बटन के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है.

1) विहगावलोकन

एफएसयू एक यूटिलिटी है जो गलत रिकॉर्ड को हटाकर एक वैध ओएलटीएएस फ़ाइल बनाने में मदद करती है। यदि आपके पास एक OLTAS फ़ाइल और उससे संबंधित त्रुटि फ़ाइल है, तो यह यूटिलिटी आपको गलत रिकॉर्ड से छुटकारा पाने और एक नई सही फ़ाइल बनाने में मदद करेगी। यह त्रुटि फ़ाइल को पढ़कर अस्वीकृत रिकॉर्ड को हटा देता है और केवल स्वत: उत्पन्न RT04 रिकॉर्ड के साथ मान्य रिकॉर्ड को मिलाकर एक नई फ़ाइल का निर्माण करता है। यह सही फ़ाइल OLTAS साइट पर अपलोड किया जा सकता है। सभी अस्वीकृत रिकॉर्ड अलग किए जाते हैं और आपके संदर्भ के लिए अन्य फ़ाइल में रखे जाते हैं।

2) क्रियात्मकता

जब आप SPECIAL_FVU.exe फ़ाइल खोलते हैं तो एक यूटिलिटी फ़ाइल नीचे दिखाई देगी

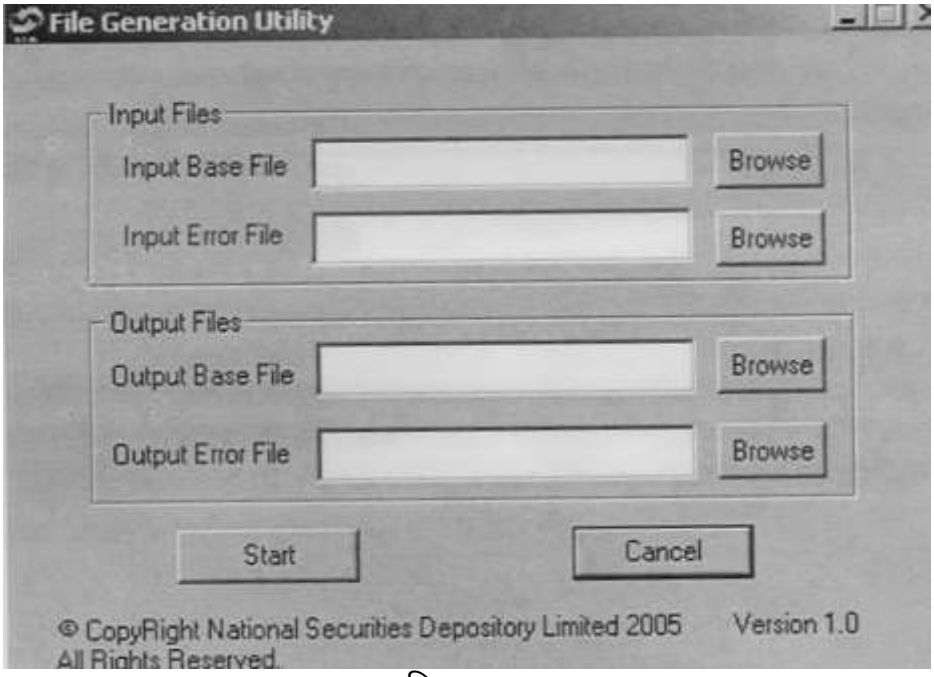

चित्र 1

यूटिलिटी में शीर्ष पर यूटिलिटी का नाम, यूटिलिटी को मिनिमाइज़ करने और बंद करने के लिए बटन, चार टेक्स्ट फ़ील्ड और "ब्राउज़" नामक चार बटन, एक स्टार्ट बटन और एक रद्द बटन शामिल हैं। एक कॉपीराइट संदेश और संस्करण संख्या भी दिखाई देगी।

उपयोगकर्ता को नीचे वर्णित सभी चार फ़ील्ड में मान्य इनपुट दर्ज करना आवश्यक है।

- **इनपुट आधारित फ़ाइल:**

आधार फ़ाइल का पूर्ण फ़ाइल का सम्पूर्ण प्रक्रिया दें। यह आधार फ़ाइल वह फ़ाइल है जिसे कुछ त्रुटियों के कारण अस्वीकार कर दिया गया है। आप ब्राउज़ बटन पर क्लिक करके फ़ाइल का चयन कर सकते हैं। यह आपको नीचे प्रदर्शित एक 'खुला' बॉक्स दिखाएगा (चित्रा 2)। आवश्यक फ़ोल्डर के लिए ब्राउज़ करें, फ़ाइल का चयन करें और फिर ओपन पर क्लिक करें.

इनपुट फ़ाइल नाम केवल "ddmmyyfv.bnk" प्रारूप में होना चाहिए।

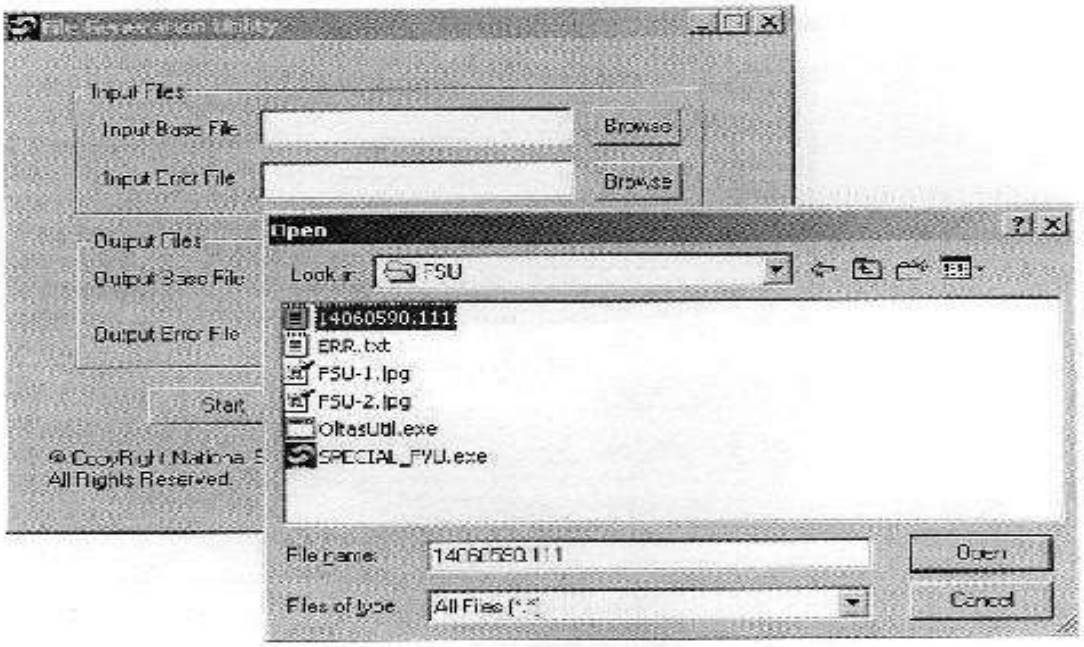

चित्र 2

फ़ाइल एक्सटेंशन में वैध बैंक कोड होना चाहिए।

बी) इनपुट त्रुटि फ़ाइल:

यह इनपुट बेस फ़ाइल के लिए त्रुटि है। (चरण 1 में चुना गया) त्रुटि फ़ाइल को ओएलटीएएस साइट से डाउनलोड किया जा सकता है और सेव किया जा सकता है। आप ओएलटीएएस लिंक सेल सुविधा द्वारा उत्पन्न त्रुटि फ़ाइल का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको त्रुटि फ़ाइल की पूरी प्रक्रिया देने की आवश्यकता है। दाईं ओर ब्राउज़ बटन का उपयोग ऊपर बताए अनुसार किया जा सकता है। त्रुटि फ़ाइल में वह फ़ाइल नाम है जिसके लिए त्रुटियाँ पाई जाती हैं. यह नाम इनपुट बेस फ़ाइल से मेल खाना चाहिए. उपयोगकर्ता को यह फ़ाइल नहीं बदलनी चाहिए. इसके अलावा यदि सही त्रुटि फ़ाइल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो निम्नलिखित संदेश दिखाया जाएगा और यूटिलिटी बंद हो जाएगी (चित्रा 3)।

इनपुट त्रुटि फ़ाइल के नाम के लिए कोई सत्यापन नहीं है.

Figure 3

नोट: आउटपुट मान्य फ़ाइल को जीन रेटेड नहीं मिलेगा यदि दो इनपुट फ़ाइलों में से किसी एक के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके अलावा FVU से उत्पन्न त्रुटि फ़ाइल या OLTAS साइट से प्राप्त स्वीकार्य है। किसी अन्य प्रारूप का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे गलत परिणाम दे सकते हैं।

सी) आउटपुट आधारित फ़ाइल:

यह आउटपुट मान्य फ़ाइल है जिसे ओएलटीएएस साइट पर अपलोड किया जा सकता है या एफ़यूवी के माध्यम से मान्य किया जा सकता है। फ़ाइल की पूरी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है. फ़ाइल नाम इनपुट बेस फ़ाइल नाम के समान हो सकता है यदि स्थान अलग है अन्यथा यह इनपुट बेस फ़ाइल पर अधिलेखित हो जाएगा। आवश्यक फ़ोल्डर में ब्राउज़िंग के लिए ब्राउज़ बटन का उपयोग करें और तब आवश्यक फ़ाइल नाम दर्ज करें. इनपुट बेस फ़ाइल और आउटपुट बेस फ़ाइल का विस्तार मेल खाना चाहिए।

ए) RT04 में फ़ील्ड MAJ_HD_CD , TOT_NO_OF_RFND, TOT_NO_OF_CHLN, TOT_NO_ERR_RFND, TOT_NO_ERR_CHLN, RFND_TOT_AMT, CHLN_TOT_AMT की गणना आउटपुट मान्य फ़ाइल में मौजूद रिकॉर्ड डेटा से की जाती है।

बी) नोडल फ़ील्ड की गणना आउटपुट मान्य फ़ाइल में मौजूद रिकॉर्ड डेटा यानी आउटपुट मान्य फ़ाइल में मौजूद विशिष्ट ZAO कोड से की जाएगी।

सी) प्रत्येक RT04 के लिए ट्रांसमिशन दिनांक आउटपुट मान्य फ़ाइल नाम के ddmmy भाग के समान होगी.

डी) RT04 का फ़ील्ड RFND_DEBIT_DT रिक्त रखा गया है.

ई) एक विशेष RT08 R / N संयोजन में, यदि किसी भी रिकॉर्ड में त्रुटि है, तो दोनों रिकॉर्ड अस्वीकार कर दिए जाएंगे और आउटपुट त्रुटि फ़ाइल में डाल दिए जाएंगे।

आउटपुट बेस फ़ाइल नाम प्रारूप "ddmmyyfv.bnk" में होना चाहिए

डी) आउटपुट त्रुटि फ़ाइल:

यूटिलिटी इस फ़ाइल में सभी अस्वीकृत रिकॉर्ड डाल देगी। उपयोगकर्ता को इस फ़ाइल के लिए पूरी प्रक्रिया देने की आवश्यकता है। इस फ़ाइल के नाम के लिए कोई सत्यापन नहीं है.

प्रारंभ बटन:

उपरोक्त सभी चार फ़ील्ड में मान्य फ़ाइल नाम दर्ज करने के बाद, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। प्रक्रिया के सफल समापन के बाद एक संदेश दिखाया जाएगा।

रद्द करें बटन:

यूटिलिटी बंद करने के लिए रद्द करें बटन का उपयोग करें।

अनुबंध III

नोडल शाखा दैनिक मुख्य स्क्रॉल (पावती) के लिए प्रारूप

1	नोडल शाखा स्क्रोल डेट (DD/MM/YYYY)
2	बीएसआर कोड
3	शाखा स्क्रोल प्राप्त करने का दिनांक (DD/MM/YYYY)
4	कुल कर राशि
5	कुल चालान की संख्या
6	डीओ –आईडी

#	प्रमुख शीर्ष
#	राशि
#	चालान की संख्या

#	प्रमुख शीर्ष
#	राशि
#	चालान की संख्या

:
:
:

यह ब्लॉक (ऊपर दिखाया गया है) को उतनी बार दोहराया जाएगा जितनी बार कर प्रमुख उपलब्ध हैं।

नोट:

1) एक प्राप्त शाखा के लिए रिकॉर्ड एक पंक्ति में निहित होना चाहिए और मूल्यों को अल्पविराम से अलग किया जाना चाहिए।

2) कैरिज रिटर्न या लाइनफीड [यानी एंटर कुंजी ()] एक प्राप्त शाखा के लिए रिकॉर्ड के अंत को इंगित करता है।

3) ब्लॉक का अनुक्रम (majhd, राशि, no_challan) आवश्यक नहीं है लेकिन बढ़ता क्रम अपेक्षित है।

4) उदाहरण

पहले छ फील्ड

ब्लॉक

30/11/2005, 0230001, 25/11/2005, 6600, 22, PNE, 0020, 200, 2, 0021, 100, 1, 0024, 300, 4,

0026, 400, 2, 0031, 500, 1, 0032, 600, 2, 0033, 700, 1, 0034, 800, 1,

0070, 900, 1, 0036, 1100, 5

विस्तृत उदाहरण

पहले छ फील्ड ब्लॉक

13/11/2005, 0000455, 12/11/2005, 5775, 18, PNE, 0020, 1525, 6, 0021, 200, 2, 0023, 100, 1, 0026, 300, 2,

0031, 600, 1, 0032, 750, 2, 0033, 550, 1, 0034, 800, 2, 0070, 950, 1 ↵

13/11/2005, 0003861, 12/11/2005, 9950, 17, PNE, 0020, 3500, 5, 0020, 2250, 3, 0023, 300, 1, 0026, 400, 1,

0031, 500, 1, 0033, 600, 2, 0032, 700, 1, 0034, 800, 2, 0070, 900, 1 ↵

13/11/2005, 0004618, 11/11/2005, 640112, 22, PNE, 0020, 629367, 20, 0021, 10745, 2 ↵

13/11/2005, 0230011, 11/11/2005, 47071, 2, PNE, 0020, 47071, 2 ↵

13/11/2005, 0230116, 10/11/2005, 304648, 20, NSK, 0020, 26942, 2, 0021, 277706, 18 ↵

13/11/2005, 0230004, 13/11/2005, 408134, 16, NSK, 0020, 407190, 15, 0021, 944, 1 ↵

5) यदि नोडल बैंक एक डीआरएस में एक ही प्राप्त शाखा के लिए दो अलग-अलग तिथियों के स्क्रॉल भेज रहा है तो उनकी प्रविष्टि डीआरएस फ़ाइल में दो अलग-अलग लाइनें होनी चाहिए जैसा की निम्न है –

14/11/2005, 0002053, 12/11/2005, 5775, 18, PNE, 0020, 1525, 6, 0021, 200, 2, 0023, 100, 1, 0026, 300, 2,

0031, 600, 1, 0032, 750, 2, 0033, 550, 1, 0034, 800, 2, 0070, 950, 1 ↵

14/11/2005, 0002053, 13/11/2005, 9950, 17, PNE, 0020, 5250, 6, 0023, 500, 2, 0024, 300, 1, 0025, 400, 1,

0031, 500, 1, 0033, 600, 2, 0033, 700, 1, 0034, 800, 2, 0070, 900, 1 ↵

14/11/2005, 0002034, 13/11/2005, 408134, 16, NSK, 0020, 407190, 15, 0021, 944, 1 ↵

- उपरोक्त डीआरएस की पहली दो पंक्तियों का निरीक्षण करें जिसमें दोनों लाइनों में एक ही नोडल शाखा स्क्रॉल तिथि और बीएसआर कोड है, जो इस मामले में आवश्यक है, लेकिन विवरण अलग-अलग हैं।

- शाखा स्क्रॉल प्राप्त करने की तिथि अलग है जो नोडल शाखा स्क्रॉल तिथि से कम होनी चाहिए।

- तीसरी पंक्ति उसी नोडल बैंक की अन्य शाखा के लिए नियमित पंक्ति है।

6) दिनांक: DD/MM/YYYY प्रारूप में दिनांक है।
बीएसआर कोड: 7 अंकों का संख्यात्मक कोड है।
डीओ –आईडी : 3-अंकीय अल्फा कोड है।
प्रमुख शीर्ष : 4 अंकों का संख्यात्मक कोड है।
चालान की राशि और संख्या संख्यात्मक मान हैं।

करदाताओं को बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले कंप्यूटर जनित रसीदों का प्रारूप प्रोफार्मा

कंप्यूटर जनित प्राप्ति (संग्रहकर्ता बैंक शाखा द्वारा प्रत्यक्ष कर के जमाकर्ता को सरकारी खाते में स्रोत पर कर जमा करने के लिए चालान फार्म सं 281 के विरुद्ध जारी किया जाएगा।		
कर संग्रहण करने वाले बैंक का नाम		
कटौतीकर्ता का पूरा नाम		
कटौतीकर्ता का टैन (**10** वर्ण)		
जमा की गई राशि :		
(i) आयकर		
(ii) अधिभार		
(iii) शिक्षा उपकर		
(iv) दण्ड		
जमा की गई कुल राशि : (आंकड़े में)		
कर जमा करने का तरीका (नकद/ डेबिट से खाते/ चेक द्वारा) असर संख्या))		
चेक के नकदीकरण की तिथि (dd/mm/yy)		
कंपनियों से आयकर कटौती/ संग्रहण के कारण (**0020**)/ कंपनियों के अलावा अन्य (**0021**)		
लघु शीर्ष - भुगतान का प्रकार - (कटौतीकर्ता द्वारा काटा गया टीडीएस / टीसीएस / वसूल किया गया / या विभाग द्वारा मांगा गया))		**200/400**
भुगतान की प्रकृति जिसमें से कर काटा जाना या वसूल किया जाना है - (अनुभाग कोड दें)		
आकलन वर्ष (yy)		
चालान पहचान संख्या (सीआईएन)		
वसूलीकर्ता बैंक शाखा का बीएसआर कोड	(**7** अक्षर)	
चेक निविदा की तिथि (dd/mm/yy)	(**8** अक्षर)	
चालान क्रम संख्या	(**5** अक्षर)	
वसूलीकर्ता बैंक शाखा के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और सील ↓		

करदाताओं को बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले कंप्यूटर जनित पावती का प्रारूप प्रोफार्मा

कंप्यूटर जनित पावती (बैंक शाखा द्वारा प्रत्यक्ष कर के जमाकर्ता को सरकारी खाते में स्रोत पर कर जमा करने के लिए चालान फार्म सं 280 के तहत जारी किया जाएगा।	
कर वसूलने वाले बैंक का नाम	
करदाता का पूरा नाम	
करदाता का पैन (**10** अक्षर)	
जमा की गई राशि :	
(i) आयकर	
(ii) अधिभार	
(iii) शिक्षा उपकर	
(iv) दण्ड	
जमा की गई कुल राशि : (आंकड़े में)	
कर जमा करने का तरीका (नकद/डेबिट से खाते/चेक द्वारा) असर संख्या))	
चेक के नकदीकरण की तिथि (dd/mm/yy)	
कंपनियों से आयकर कटौती/ संग्रहण के कारण (**0020**)/ कंपनियों के अलावा अन्य (**0021**)	
लघु शीर्ष- भुगतान का प्रकार	
आकलन वर्ष (yy)	
चालान पहचान संख्या (सीआईएन)	
वसूलीकर्ता बैंक शाखा का बीएसआर कोड (**7** वर्ण)	
चेक निविदा की तिथि (dd/mm/yyyy) (**8** वर्ण)	
चालान सीरियल नंबर (**5** वर्ण)	
बैंक शाखा एकत्र करने के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर ↓	

मैं घर/कार्यालय में बैठकर ऑनलाइन कर भुगतान कैसे कर सकता हूं?

ऊपर सूचीबद्ध किसी भी बैंक के साथ नेट-बैंकिंग खाता खोलें।

- वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाएं, 'ऑनलाइन करों का भुगतान करें' पर क्लिक करें।
- आवश्यक चालान ऑनलाइन भरें। सहायता के लिए स्क्रीन पर FAQ, डाउनलोड आदि के रूप में उपलब्ध है।
- नेट-बैंकिंग खाते के माध्यम से ऑनलाइन कर भुगतान करें।
- एक चालान काउंटरफॉइल सीआईएन (चालान पहचान संख्या) के साथ स्क्रीन पर तुरंत उपलब्ध होगा। इस काउंटरफॉइल पर चालान पहचान संख्या (सीआईएन) को आय रिटर्न में उद्धृत किया जाना चाहिए।
- काउंटरफॉइल प्रिंट करें और यदि संभव हो तो इसे कंप्यूटर में भी सेव करें।
- जांचें कि क्या आपका भुगतान आयकर विभाग के पास https://tin.tin.nsdl.com/oltas/servlet/QueryTaxpayer इस लिंक पर उपलब्ध है।

ऑनलाइन करों का भुगतान करने के क्या फायदे हैं?

- आप अपने नेट-बैंकिंग खाते के माध्यम से किसी भी समय किसी भी स्थान से करों का भुगतान कर सकते हैं।
- अपने खाते से धन का त्वरित हस्तांतरण।
- ई-चालान पर आप जो लिखेंगे वह सीधे आयकर विभाग को भेजा जाएगा। बैंक कोई डेटा एंट्री नहीं करेंगे।
- आप चालान कॉपी और रसीद कॉपी को सेव/प्रिंट कर सकते हैं।
- जैसे ही आपका बैंक राशि के भुगतान को अधिकृत करता है, आपको अपने बैंक से एक स्पष्ट, सुस्पष्ट रसीद / काउंटरफॉइल प्राप्त होगा।
- ई-पेमेंट ट्रांजेक्शन की ट्रांजैक्शन आईडी आपके बैंक स्टेटमेंट में आपके लिए उपलब्ध होगी।
- आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा वास्तव में आयकर विभाग में पहुंचा है या नहीं। इसके लिए आपको टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क वेबसाइट पर जाना होगा: https://tin.tin.nsdl.com/oltas/index.html

और बॉक्स पर क्लिक करें	CIN Based view

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया जाएं: incometaxindia.gov.in **ऑनलाइन करों का भुगतान करें**

महत्वपूर्ण : बकाया मांग के विरुद्ध समायोजित धन वापसी के मामले में, सामान्य धन वापसी को चालान के साथ संलग्न किया जाना चाहिए और पहले की प्रक्रिया के अनुसार लेखा अधिकारियों द्वारा बैंक को भेजा जाना चाहिए।

मास्टर परिपत्र - सूचकांक

क्रम संख्या	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	डीजीबीए. जीएडी. सं. एच-684/42.01.001/2003-04	09.01.2004	पिंक बुक 'प्रत्यक्ष करों के लिए लेखा प्रणाली' में संशोधन
2.	आरबीआई/2004/131 डीजीबीए जीएडी. सं 1008/42.01.034/2003-04	01.04.2004	ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) की शुरुआत - चालान की प्रतियों पर रबर स्टैंप की ब्रांडिंग
3.	आरबीआई/2004/135 डीजीबीए जीएडी. सं 1142/42.01.001/2003-04	02.04.2004	बैंक शाखाओं में करों के संग्रह की प्रक्रिया - ग्राहक सेवा
4.	आरबीआई/2004/145 डीजीबीए जीएडी. सं एच-1068/42.01.034/2003-04	16.04.2004	ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओएलटीएएस) के लिए लेखा प्रक्रिया
5.	आरबीआई/2004/184 डीजीबीए जीएडी. सं एच-1114/42.01.034/2003-04	29.04.2004	1 जून, 2004 से ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली का कार्यान्वयन
6.	आरबीआई/2004/213 डीजीबीए. जीएडी. सं No.H - 1169/42.01.034/2003-04	22.05.2004	ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओएलटीएएस) से संबंधित लेखा प्रक्रिया - स्पष्टीकरण
7.	आरबीआई/2004/75 डीजीबीए. जीएडी.सं-एच-69/42.01.034/2004-05	28.07.2004	ऑन-लाइन टैक्स लेखांकन प्रणाली (ओएलटीएएस) - एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डेटा का ट्रांसमिशन -सत्यापन जाँच
8.	आरबीआई/2004/181 डीजीबीए. जीएडी. सं - एच-235/42.01.034/2004-05	15.09.2004	ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (OLTAS) - शाखाओं की भागीदारी
9.	आरबीआई/2004/164 डीजीबीए. जीएडी. सं एच-170/42.01.034/2003-04	04.09.2004	बैंकों द्वारा ओएलटीएएस डेटा के डेटा कैप्चर के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दे
10.	आरबीआई/2004/300 डीजीबीए जीएडी. सं 2532-65/42.01.034/2004-05	14.12.2004	दिनांक 1-1-2005 से चालान पर स्थायी खाता संख्या (पैन)/कर कटौती खाता संख्या (टैन) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना
11.	आरबीआई/2004/326 डीजीबीए. जीएडी. सं 3278-3311/42.01.034/ 2004-05	31.12.2004	सीबीडीटी बकाया के संग्रह के लिए उप-एजेंसी व्यवस्था का उन्मूलन
12.	आरबीआई/2005/411 डीजीबीए जीएडी. सं एच-5287/42.01.034/2004-05	01.04.2005	ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओएलटीएएस) - सीबीडीटी संग्रह को सरकारी खाते में जमा करने से संबंधित लेखा प्रक्रिया

13.	आरबीआई 2005/412 डीजीबीए. जीएडी. सं एच-5318/42.01.034/2004-05	04.04.2005	प्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए बैंक शाखाओं का अधिकार रद्द
14.	आरबीआई/2005/466 डीजीबीए जीएडी. सं 5801/42.01.034/2004-05	13.05.2005	ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली – निधि निपटान
15.	आरबीआई/2005/39 डीजीबीए जीएडी. सं एच-42/42.01.034/2005-06	04.07.2005	वित्त अधिनियम 2005- प्रमुख शीर्ष और चालान में परिवर्तन
16.	आरबीआई/2005/81 जीएडी. सं.382/42.01.0 34/2005-06	26.07.2005	OLTAS - कर सूचना नेटवर्क (TIN) द्वारा विकसित फ़ाइल पृथक्करण उपयोगिता
17.	आरबीआई/2005/265 डीजीबीए. जीएडी. सं एच-8824/42.01.034/2005-06	28.12.2005	स्थायी खाता संख्या (पैन)/कर कटौती खाता संख्या (टैन) का अनिवार्य उल्लेख - राजस्थान राज्य
18.	डीजीबीए जीएडी. सं एच 8294/42.01.037/2005-06	14.12.2005	ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली - करदाता द्वारा चेक का आहरण - प्राप्तकर्ता का नाम
19.	डीजीबीए. जीएडी. सं एच 8649/42.01.034/2005-06	23.12.2005	ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओएलटीएएस) - बैंकों में सॉफ्टवेयर सत्यापन
20.	आरबीआई/2006/295 डीजीबीए जीएडी. सं एच 11140/42I 01.034/2005-06	02.02.2006	ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (OLTAS) - ZAOs को ई-मेल द्वारा दैनिक स्क्रॉल भेजना
21.	आरबीआई/2006/55 डीजीबीए जीएडी. सं. एच-161/42.01.034/2005-06	07.07.2006	ओएलटीएएसएस - पैन/टैन का सत्यापन
22.	आरबीआई/2006/150 डीजीबीए. जीएडी. सं. एच-6226/42.01.011/2006-07	10.10.2006	सरकारी राजस्व के प्रेषण की अनुमेय अवधि
23.	आरबीआई/2007/235 डीजीबीए जीएडी. सं. एच नं11763/42.01.011/2006-07	24.01.2007	सरकारी प्राप्तियों के प्रेषण में देरी - विलंबित अवधि ब्याज
24.	आरबीआई/2007/286 डीजीबीए जीएडी. सं 13742/42.01.011/2006-07	13.03.2007	सरकारी प्राप्तियों के प्रेषण में देरी - विलंबित अवधि ब्याज
25.	डीजीबीए जीएडी. सं 3774/42.01.034/2007-08	09.10.2007	टिन पर अपलोड किए गए चालान विवरण में विसंगतियां
26.	आरबीआई/2007/206 डीजीबीए जीएडी. सं 6212/42.01I 034/2007-08	06.12.2007	ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओएलटीएएस) - डेटा गुणवत्ता में त्रुटियाँ

27.	आरबीआई/2008/275 डीजीबीए जीएडी. सं 10577/42.01.038/2007-08	03.04.2008	सरकारी राजस्व से संबंधित ई-भुगतान लेनदेन के लिए कट-ऑफ समय
28.	आरबीआई/2008/280 डीजीबीए जीएडी. सं एच-10875/42.01.038/2007-08	10.04.2008	01.04.2008 से करदाताओं की श्रेणियों द्वारा कर का अनिवार्य ई-भुगतान
29.	आरबीआई/2008/321 डीजीबीए. जीएडी. सं एच-11895/42.01.038/ 2007-08	15.05.2008	आईटी अधिनियम की धारा 44एबी के तहत आने वाले कॉर्पोरेट और करदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष करों का अनिवार्य ई-भुगतान
30.	आरबीआई/2008/328 डीजीबीए. जीएडी. सं एच-12070/42.01.034/ 2007-08	22.05.2008	डेटा की गुणवत्ता में सुधार –जून 2008 से कम्प्यूटरीकृत प्राप्तियों की शुरूआत।
31.	डीजीबीए जीएडी. सं एच No.H.551/42.01.011/2008-09	18.07.2008	सरकारी लेन-देन के ई-भुगतान के विप्रेषण की अनुमेय अवधि – निजी क्षेत्र के बैंक
32.	आरबीआई/2009/463 डीजीबीए. जीएडी संख्या एच -9284/42.01.011/2008-09	28.04.2009	सरकारी खातों में सरकारी प्राप्तियों के प्रेषण में देरी पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ब्याज की पुन: प्राप्ति
33.	आरबीआई/2009-10/381 डीजीबीए. जीएडी संख्या एच 7790/42.01.011/2009-10	06.04.2010	सरकार में सरकारी राजस्व के प्रेषण के लिए अनुमेय अवधि दूरस्थ इलाके, कठिन और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए खाता
34.	आरबीआई/2010-11/229 डीजीबीए. जीएडी संख्या एच 2444/42.01.011/2010-11	08.10.2010	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सरकारी खाते में ई-भुगतान के प्रेषण के लिए अनुमेय अवधि
35.	आरबीआई/2014-15/416 डीजीबीए. जीएडी संख्या एच 3203/42.01.011/2014-15)	21.01.2015	क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से सरकारी खाते में प्रेषण के लिए अनुमेय अवधि